भाद्रपद कृष्ण - 4 ■ संवत 2081 ■ वर्ष - 12 ■ अंक - 31 ■ पृष्ठ - 8 ■ रु. 5/- चेन्नई » शुक्रवार » 23-08-2024 ■ www.dakshinbharat.com ■ Email : chennai@dakshinbharat.com

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷின் பாரத் ராஷ்ட்ரமத் | தினசரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बेंगलूरु से एक साथ प्रकाशित

5 राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 बहाल करना चाहते हैं : गिरिराज सिंह

6 कानून का खौफ होता तो नहीं होता कोलकाता कांड

7 'रेस 4' में काम करेंगे सैफ अली खान!

फर्स्ट टेक

कर्नाटक सरकार ने जेएसडब्ल्यू स्टील को 3,667 एकड़ जमीन बेचने को मंजूरी दी

बेंगलूरु/भाषा। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को बेल्लारी जिले में जेएसडब्ल्यू स्टील को कुल 3,667.31 एकड़ भूमि की प्रस्तावित बिक्री को अपनी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने बेंगलूरु में दो बड़ी परियोजनाओं- एक स्काई डेक (ऊंचा मनोरम मंच या इमारत) और एक भूमिगत वाहन सुरंग के लिए भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, इसे जेएसडब्ल्यू स्टील के पक्ष में संदुर तालुक के कुरेकुप्पा और तोरानागल्ल गांवों में 2,000.58 एकड़ भूमि और तोरानागल्ल, मुसिनायाकनहल्ली और येराबनहल्ली की 1,666.73 एकड़ भूमि के लिए एक पूर्ण बिक्री विलेख निष्पादित करने की मंजूरी दे दी गई है।

हिमाचल में अचानक आई बाढ़ के कारण 14 पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त

नई दिल्ली/भाषा। हिमाचल प्रदेश में 25 जुलाई से अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 14 पनबिजली (जलविद्युत) परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें से कुछ पिछले 10 वर्षों में कई बार प्रभावित हुई हैं। एक विश्लेषण में यह जानकारी दी गई। अचानक आई बाढ़ और बादल फटने से जलविद्युत परियोजनाओं को होने वाला नुकसान की निरंतर पुनरावृत्ति हो रही है, जिसका असर लोगों और बिजली उत्पादन दोनों पर पड़ता है। विशेषज्ञ ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले आपदा जोखिम विश्लेषण किए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं। विशेषज्ञों ने बेहतर आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों की स्थापना की भी सिफारिश की हैं।

'एअर इंडिया' की उड़ान में बम की धमकी अफवाह साबित हुई

तिरुवनंतपुरम/भाषा। मुंबई से आ रहे एअर इंडिया के एक विमान के शौचालय में बम की धमकी वाला संदेश जांच में अफवाह साबित हुआ। पुलिस के मुताबिक बम की धमकी के बाद बृहस्पतिवार को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पूर्ण आपातकाल घोषित कर दिया गया था। तिरुवनंतपुरम पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह धमकी अफवाह साबित हुई। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सघन तलाशी किये जाने के दौरान विमान में कोई विस्फोटक नहीं मिला। हवाई अड्डा सूत्रों के अनुसार हवाई अड्डे पर सुबह घोषित की गयी आपात स्थिति अपराह्न करीब 12 बजकर 10 मिनट पर हटा ली गयी।

सूर्यास्त	सूर्योदय
23-08-2024 6:25 बजे	24-08-2024 5:57 बजे

BSE	NSE
81,053.19 (+147.89)	24,811.50 (+41.30)

सोना	चांदी
7,382 रु. (24 कैरेट) प्रति ग्राम	89,000 रु. प्रति किलो

मिशन मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com

कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

धर्मान्तरण

धर्म नहीं पूजा पहनावा,
नियम दिखावा या मंचन।
सत्ता ताकत भय से बदले,
कहलाते वे गठबंधन।
धर्म स्वयं धारित करता नर,
हो जिससे आनंदित मन।
जबरन धर्म बदलने वाले,
निज धर्मों के हैं दुश्मन।।

मोदी-टस्क वार्ता में भारत, पोलैंड ने पंचवर्षीय 'कार्य योजना' का अनावरण किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वारसॉ/भाषा। भारत और पोलैंड ने बृहस्पतिवार को अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके पोलिश समकक्ष डोनाल्ड टस्क के बीच व्यापक वार्ता के बाद कुशल श्रमिकों की आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए।

बैठक में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा संबंधों को महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित करने का संकल्प व्यक्त किया। टस्क ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने के नई दिल्ली के प्रयासों में एक प्रमुख भागीदार बनने की वारसॉ की इच्छा भी व्यक्त की।

मोदी बुधवार को पोलैंड की राजधानी पहुंचे। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की लगभग आधी सदी में पोलैंड की पहली यात्रा है। दो देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मोदी शुक्रवार को कीव में करीब सात घंटे रहेंगे।

प्रधानमंत्री ने पोलिश राष्ट्रपति आंद्रजेज डूडा के साथ भी बातचीत की।

मोदी-टस्क वार्ता के बाद, दोनों पक्षों ने भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी के लिए एक पंचवर्षीय ''कार्य योजना'' (2024-2028) का अनावरण किया, जिसमें सहयोग के लिए रक्षा, व्यापार, कृषि-तकनीक, ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स और खनन सहित कई क्षेत्रों की पहचान की गई।

टस्क की मौजूदगी में मोदी ने मीडिया में दिये अपने बयान में कहा, ''इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदलने का निर्णय लिया है।'' उन्होंने कहा, ''आज हमने अपने संबंधों को नई दिशा देने के लिए कई पहलों की पहचान की है।''

'कार्य योजना' में राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, परिवहन और संपर्क, जलवायु, ऊर्जा, खनन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा यूरोपीय संघ-भारत सहित विभिन्न स्तंभों के अंतर्गत सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है।

इसमें विशेष रूप से चल रही भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश वार्ता के शीघ्र समापन, भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद (टीटीसी) के संचालन और भारत-यूरोपीय संघ संपर्क साझेदारी के कार्यान्वयन का समर्थन करने का उल्लेख किया गया।

अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता कार्यबल की आवाजाही को बढ़ावा देगा तथा उनका कल्याण सुनिश्चित करेगा।

प्रधानमंत्री ने 2022 में संघर्ष शुरू होने के बाद यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने में सहायता करने के लिए पोलैंड को धन्यवाद भी दिया।

प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए

वारसॉ/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पोलैंड की अपनी दो दिवसीय ''परिणामजनक'' यात्रा के संपन्न होने के बाद बृहस्पतिवार को यूक्रेन की ऐतिहासिक यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पोलैंड के नेतृत्व के साथ व्यापक वार्ता की।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 'एक्स' पर कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पोलैंड की अपनी परिणामजनक यात्रा पूरी की जो द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मील का पत्थर है। चार दशकों के बाद प्रधानमंत्री की यह उच्चस्तरीय यात्रा भारत-पोलैंड संबंधों को व्यापक और प्रगाढ़ बनाएगी।''

राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा पर गये मोदी ने कहा है कि वह जारी संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान को लेकर यूक्रेनी नेता के साथ अपने विचार साझा करेंगे।

शांति बहाल करने के लिए भारत हरसंभव सहयोग देने को तैयार : मोदी ने जेलेंस्की से वार्ता से पहले कहा

वारसॉ/भाषा। युद्धग्रस्त यूक्रेन की अपनी बहुप्रतीक्षित यात्रा से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत का दृढ़ता से मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं किया जा सकता और यह (भारत) क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के लिए हरसंभव सहयोग देने को तैयार है। मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ व्यापक वार्ता करने के बाद यह बात कही। एक संयुक्त वक्तव्य के अनुसार, दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन किये जाने के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि सभी देशों को किसी भी राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग करने या उसे खतरे में डालने से बचना चाहिए।

मोदी ने मीडिया से कहा कि यूक्रेन और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ''हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है।'' उन्होंने कहा, ''भारत का दृढ़ता से मानना है कि युद्ध के मैदान में किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। किसी भी संकट में निर्दोष लोगों की जान जाना पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है।'' उन्होंने कहा, ''हम शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल कराने के लिए बातचीत और कूटनीति का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हरसंभव सहायता देने के लिए तैयार है।''

अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़, तीन राज्यों से 11 लोग गिरफ्तार

- मॉड्यूल का नेतृत्व रांची (झारखंड) का डॉ. इश्तियाक नामक व्यक्ति कर रहा था तथा उसकी देश के भीतर 'खिलाफत' की घोषणा करने और बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा थी।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 11 लोगों को गिरफ्तार कर एवं तीन लोगों को हिरासत में लेकर अलकायदा के एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का बृहस्पतिवार को दावा किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद इन राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर एक अभियान चलाया गया।

पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, राजस्थान के भिवाड़ी से छह लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण लेते समय गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि इन लोगों की पहचान हसन अंसारी, इनामुल अंसारी, अल्ताफ अंसारी, अरशद खान, उमर फारूक और शाहबाज अंसारी के रूप में हुई है तथा वे सभी झारखंड के मूल निवासी हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग पिछले कुछ दिन से राजस्थान में रह रहे थे। अधिकारी ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के बाद पांच और लोग झारखंड के रांची से गिरफ्तार किए गए जिनकी पहचान डॉ. इश्तियाक अहमद, मोतिउर, रिजवान, मुफ्ती रहमतुल्लाह और फैजान के रूप में हुई है।

दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा, ''मॉड्यूल का नेतृत्व रांची (झारखंड) का डॉ. इश्तियाक नामक व्यक्ति कर रहा था तथा उसकी देश के भीतर 'खिलाफत' की घोषणा करने और बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा थी।''

खाद्य सुरक्षा नियामक का दूध, दही से 'ए-वन', 'ए-टू' के दावों को हटाने का आदेश

नई दिल्ली/भाषा। खाद्य सुरक्षा नियामक एफएसएसएआई ने बृहस्पतिवार को ई-कॉमर्स सहित खाद्य कंपनियों को पैकेट से 'ए-वन' और 'ए-टू' प्रकार के दूध, दही समेत अन्य उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया। नियामक ने इस तरह के 'लेबल' को भ्रामक बताया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने कहा कि ये दावे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप नहीं हैं। अपने ताजा आदेश में, एफएसएसएआई ने कहा कि उसने इस मुद्दे की जांच की है और पाया है कि ए-वन और ए-टू का अंतर दूध में बीटा-केसीन प्रोटीन की संरचना से जुड़ा हुआ है। हालांकि, मौजूदा एफएसएसएआई नियम इस अंतर को मान्यता नहीं देते हैं। खाद्य व्यवसाय परिचालकों का जिक्र करते हुए नियामक ने कहा, ''एफबीओ को अपने उत्पादों से ऐसे दावों को हटाने का निर्देश दिया गया है।''

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को प्रसिद्ध जीव रसायन वैज्ञानिक और बेंगलूरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंदराजन पद्मनाभन को पहले 'विज्ञान रत्न पुरस्कार' से सम्मानित किया। सरकार ने विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस सर्वोच्च पुरस्कार की इस साल शुरुआत की है।

राष्ट्रपति भवन के 'गणतंत्र मंडपम' में आयोजित पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने 13 विज्ञान श्री पुरस्कार, 18 विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और एक विज्ञान टीम पुरस्कार भी प्रदान किये।

चंद्रयान-3 मिशन पर काम करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की टीम को 'विज्ञान टीम' पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुरस्कार मिशन के परियोजना निदेशक पी वीरमुथुवेल ने प्राप्त किया।

सभी पुरस्कार विजेताओं को उनके संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए एक पदक और प्रशस्ति पत्र दिया गया।

'विज्ञान श्री' पुरस्कार से सम्मानित किये गये वैज्ञानिकों में बेंगलूरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की निदेशक अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम; तिरुवनंतपुरम स्थित राष्ट्रीय अंतर्विषयी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक आनंदरामकृष्णन सी; भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान में रसायन विज्ञान समूह के निदेशक आवेश कुमार त्यागी; लखनऊ स्थित सीएसआईआर-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी शामिल हैं।

चिकित्सक बलात्कार-हत्या मामला:

न्यायालय ने जांच में 'खामियों' के लिए कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को सख्त लहजे में कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक से कथित तौर पर बलात्कार एवं उसकी हत्या के संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज करने में कोलकाता पुलिस की देरी ''बेहद व्यथित करने वाली'' है। न्यायालय ने घटनाओं के क्रम तथा प्रक्रियागत औपचारिकताओं के समय को लेकर भी सवाल उठाए।

न्यायालय ने इस घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील भी की। न्यायालय ने कोलकाता की एक चिकित्सक की मौत के मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि ''न्याय और औषधि'' को रोका नहीं जा सकता। न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया कि वे देशभर में चिकित्सकों की सुरक्षा को संस्थागत बनाने के लिए तत्काल कदम उठाएं।

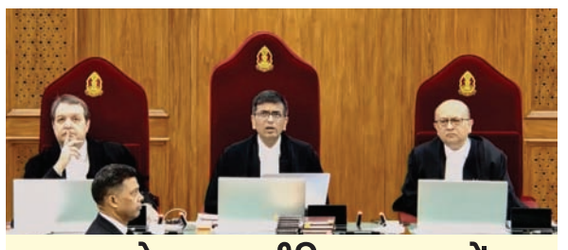

मामले का राजनीतिकरण न करें, कानून अपना काम करेगा : न्यायालय

नई दिल्ली/भाषा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राजनीतिक दलों से कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले का राजनीतिकरण नहीं करने को कहा। इसने यह भी कहा कि मामले में ''कानून अपना काम करेगा''। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि सभी राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि कानून अपना काम करेगा।

पीठ ने चिकित्सकों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया।

उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए उसकी जांच में ''खामियों'' को उजागर किया। इस दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्थानीय पुलिस मामले को दबाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि जब तक संघीय एजेंसी ने जांच अपने हाथ में ली, तब तक अपराध स्थल का परिदृश्य ''बदल'' चुका था। उच्चतम न्यायालय ने इस बात को लेकर हैरानी जताई कि मृत चिकित्सक का पोस्टमार्टम नौ अगस्त को शाम छह बजकर 10 मिनट से शाम सात बजकर 10 मिनट के बीच किया गया और इसके बाद मामला अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज किया गया। न्यायालय ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में 14 घंटे की ''अस्पष्ट'' देरी के लिए कोलकाता पुलिस की खिंचाई की।

जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और 'इंडि' गठबंधन की प्राथमिकता : राहुल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' ('इंडिया') की प्राथमिकता है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिलें। उन्होंने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के बाद संवाददाताओं से कहा, ''कांग्रेस पार्टी और 'इंडि' गठबंधन की प्राथमिकता है कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। हमें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले ऐसा कर दिया जाएगा, लेकिन ठीक है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। '' उन्होंने कहा, ''यह आगे का कदम है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार बहाल किए जाएंगे।''

कांग्रेस नेता ने कहा कि उनका जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ 'बहुत गहरा रिश्ता' है और यहां आना उनके लिए हमेशा प्रसन्नता का विषय होता है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस हमेशा उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है।

आमजन के लाभ के लिए मिलकर काम करें बैंक अधिकारी : वित्तमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर/भाषा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारी 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने स्थानीय संपर्कों को मजबूत करें।

साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं के माध्यम से आमजन को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक के सभी अधिकारियों को समन्वय से काम करने की अपील की।

वे उदयपुर में पश्चिम-मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं।

आधिकारिक बयान के अनुसार सीतारमण ने बैठक में कहा, बैंकिंग पहुंच बढ़ाने के लिए आरआरबी के अधिकारी 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने के लिए अपने स्थानीय संपर्कों को मजबूत करें। उन्होंने सरकार की योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बैंक के सभी अधिकारियों को समन्वय से काम करने की अपील की। इस समीक्षा बैठक में पश्चिम-मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन और उनके प्रायोजित बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) शामिल हुए थे।

बयान के अनुसार, बैठक में बैंकों में आ रहीं चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने को लेकर चर्चा की गई एवं बैंकों की पिछले वित्त वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं प्रगति की समीक्षा भी की गई।

एकनाथ खडसे ही भाजपा में वापसी के बारे में बता सकते : केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे

मुंबई/भाषा। केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे ने कहा कि केवल उनके ससुर और राकांपा के पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) एकनाथ खडसे ही भाजपा में फिर से शामिल होने की अपनी योजना का खुलासा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भाजपा के दिग्गज नेताओं में से एक रहे एकनाथ खडसे को 2016 में भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया। खडसे ने 2020 में पार्टी छोड़ दी और शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा (अविभाजित) में शामिल हो गए। खडसे ने इस साल अप्रैल में राकांपा के विधान परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था और ऐसी अटकलें थीं कि वह फिर से भाजपा में शामिल हो रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर कंटेनर रखरखाव क्षमता बढ़ाने का काम जारी : सोनोवाल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह (जेएनपीए) पर कंटेनर रखरखाव सुविधा को बढ़ाकर एक करोड़ टीईयू किया जा रहा है।

बंदरगाह पर विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं की समीक्षा के बाद मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में आगामी वधावन बंदरगाह से क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा।

सभी मौसमों के अनुकूल बंदरगाह के रूप में निर्मित होने वाले इस 'ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट मेगा पोर्ट' पर 76,200 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि जेएनपीए की कंटेनर रखरखाव क्षमता जल्द ही करीब एक करोड़ टीईयू (ट्वेंटी फुट इक्विवेलेंट यूनिट) हो जाएगी। जेएनपीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंटेनर रखरखाव क्षमता वर्तमान में 74 लाख टीईयू है, जो अगले वर्ष अप्रैल तक बढ़कर 1.4 करोड़ टीईयू हो जाएगी। सोनोवाल ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का पहला 100 प्रतिशत सार्वजनिक निजी भागीदारी (लैंडलॉर्ड) वाला पहला बंदरगाह बन गया है। उन्होंने कहा, '' हमारा लक्ष्य इस सुविधा पर बड़े से बड़े जहाजों को लाना है।''

मंत्री ने कहा कि बंदरगाह ने गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा विकसित किया है और यह एक पर्यावरण-अनुकूल बंदरगाह बनने जा रहा है।

एक 'लैंडलॉर्ड' बंदरगाह एक भूस्वामी और नियामक निकाय के रूप में काम करता है, जबकि निजी कंपनियां बंदरगाह संचालन को संभालती हैं। जेएनपीए ने दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की भी घोषणा की। इसमें एक समझौता ज्ञापन जेएनपीए, वधावन बंदरगाह और आरईसी के बीच विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन हेतु ऋण वितरण से संबंधित है। दूसरा समझौता जेएनपीए और गेटवे टर्मिनल्स इंडिया (जीटीआई) के बीच जहाजों के लिए तटीय बिजली आपूर्ति के कार्यान्वयन के लिए है। दोनों समझौता ज्ञापनों पर मंत्री की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

मंत्री ने स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाने तथा कार्यबल विकास को बढ़ावा देने के लिए आईएनपीएटी द्वारा विकसित वधावन कौशल कार्यक्रम के लिए एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी पेश किया। यह कौशल कार्यक्रमों तक पहुंच को सुगम बनाने, वधावन बंदरगाह के बारे में जानकारी मुहैया करने के अलावा अन्य चीजों के लिए तैयार किया गया है। सोनोवाल ने कहा कि सरकार ने सागरमाला परियोजना के तहत अब तक 230 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं, जबकि 220 अन्य परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

सरकार ने 'सी प्लेन' परिचालन के लिए सरल मानदंडों की घोषणा की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नागर विमानन मंत्रालय ने 'सी प्लेन' परिचालन के लिए सरल नियमों की बृहस्पतिवार को घोषणा की। इसमें गैर-अनुसूचित इकाइयों को ऐसी सेवाएं संचालित करने की अनुमति देना और आसान प्रमाणपत्र प्रक्रिया लागू करना शामिल है।

इन सरल किए गए मानदंडों का मकसद क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत 'सी प्लेन' परिचालन को बढ़ावा देना है। 'सी प्लेन' सामान्यतः ऐसे विमान होते हैं जो समुद्र पर उड़ान भर सकते हैं और उतर सकते हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के सरल मानदंडों के तहत, 'वाटरड्रोम लाइसेंस' की आवश्यकता नहीं होगी तथा अनुपालन आवश्यकताओं को भी कम कर दिया गया है। 'वाटरड्रोम' जल क्षेत्र में विमान के उतरने और उड़ान भरने की जगह को कहा जाता है।

नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि संशोधित नियमों को व्यापक विचार-विमर्श के बाद सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। संशोधित नियमों की घोषणा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में नायडू ने कहा कि 'सी प्लेन' परिचालन से पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।

अन्य विनियामक बदलावा के अलावा, नए वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (सीपीएल) धारक अब सीधे 'सी प्लेन रेटिंग' प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उन्हें इसे उड़ाने की अनुमति मिल जाएगी।

मंत्रालय के अनुसार, सरल दिशानिर्देश गैर-अनुसूचित संचालकों (एनएसओपी) को 'सी प्लेन' परिचालन की अनुमति देंगे।

भारत ने अंडमान एवं निकोबार के साथ-साथ गुजरात में भी 'सी प्लेन' परिचालन शुरू किया था, लेकिन यह लंबे समय तक जारी नहीं रह पाया।

इस कार्यक्रम में नागर विमानन सचिव वुमलुनमंग वुअलनाम ने कहा कि 'सी-प्लेन' के लिए नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) को सुव्यवस्थित कर दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकारों से 'सी-प्लेन' परिचालन के लिए जल क्षेत्रों की तलाश करने का आह्वान किया।

वुअलनाम ने कहा कि लोगों को संपर्क सुविध प्रदान करने में 'सी प्लेन' एक और माध्यम होगा। उड़ान एक 'अग्रणी' योजना रही है और तीन वर्षों में 100 से अधिक मार्ग पर परिचालन शुरू किया गया है।

इसके साथ ही सरकार अंडमान एवं निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा, असम, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 18 स्थानों पर जल क्षेत्र में हवाई अड्डे स्थापित करने की योजना भी बना रही है।

हम ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नहीं: गोयल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि चाहता है कि वे निष्पक्ष और ईमानदार रहें।

ई-कॉमर्स कंपनियों के बारे में चिंता जताने के अगले दिन गोयल ने कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वालों को प्रतिस्पर्धा करने का 'उचित अवसर' सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

गोयल ने बुधवार को ई-कॉमर्स कंपनियों की बाजार खराब करने वाली कीमतों के बारे में चिंता जताई और देश में छोटे खुदरा विक्रेताओं पर उनके संचालन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताई थी। उन्होंने अपनी आशंकाओं को सार्वजनिक रूप से भी व्यक्त किया और ई-कॉमर्स क्षेत्र के बड़े पैमाने पर वृद्धि के साथ 'बड़े सामाजिक व्यवधान' की चेतावनी दी। गोयल ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि हम एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) लाना चाहते हैं, हम प्रौद्योगिकी को आमंत्रित करना चाहते हैं, हम दुनिया का सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं और हम ऑनलाइन के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, देश हमेशा यही चाहता है कि ग्राहकों के प्रति निष्पक्ष व्यवहार हो, ईमानदारी बरती जाए, वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के प्रति ईमानदारी हो और यह सुनिश्चित हो कि अन्य लोगों को भी ऐसे ऑनलाइन व्यापार के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिले। गोयल ने कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र में गति और सुविधा जैसे 'बड़े लाभ' हैं। गोयल ने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि ऐसी कंपनियां देश के लोगों की सेवा करें।

लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य : बंबई उच्च न्यायालय

मुंबई/भाषा। बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि लापता बच्चों और महिलाओं का पता लगाना सरकार का कर्तव्य है। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को ऐसे मामलों से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अदालत ने मानव तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) से भी जवाब मांगा तथा इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (एमएससीडब्ल्यू) से सुझाव आमंत्रित किए।

सांगली निवासी शाहजी जगताप की ओर से दायर जनहित याचिका में राज्य पुलिस को 2019 और 2021 के बीच महाराष्ट्र में लापता हुईं एक लाख से अधिक महिलाओं का पता लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों में राज्य के अधिकारियों द्वारा बरती जा रही 'निष्क्रियता' पर चिंता जताई गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता मंजरी पारसनीस ने बृहस्पतिवार को अदालत को सूचित किया कि जगताप की अपनी बेटी लापता है। अधिवक्ता ने बताया कि बेटी की तलाश के दौरान उनके मुवक्किल को 14 मार्च, 2023 को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े मिले; जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में लापता बच्चों की संख्या 'बहुत अधिक' है। मंत्रालय के मुताबिक, 2019, 2020 और 2021 में, लापता बच्चों की संख्या क्रमशः 4,562, 3,356 और 4,129 थी।

लद्दाख में बस खाई में गिरने से छह लोगों की मौत, 22 घायल

लेह/भाषा। लद्दाख के लेह जिले में एक बस के सड़क से 200 फुट गहरी खाई में गिरने से छह लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लेह के उपायुक्त संतोष सुखदेव ने बताया कि बस में एक स्कूल के कर्मचारी थे जो एक विवाह समारोह में जा रहे थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान दुर्बुक इलाके में बस खाई में गिर गई। अधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस कर्मियों ने घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। हेलीकॉप्टरों की मदद से 22 घायलों को एसएनएम अस्पताल और लेह स्थित सेना अस्पताल ले जाया गया। सुखदेव ने बताया कि घायलों में से दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

अदाणी मामले में जेपीसी जांच की मांग पर बीआरएस अपना रुख स्पष्ट करे : मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने बृहस्पतिवार को मांग की कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे पर और अदाणी समूह की कथित धोखाधड़ी की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन पर अपना रुख स्पष्ट करें।

तेलंगाना कांग्रेस के प्रमुख रेड्डी ने अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों और पार्टी विधायकों के साथ सेबी प्रमुख माधवी बुच के इस्तीफे और अदाणी की कथित वित्तीय धोखाधड़ी की जेपीसी से जांच की मांग को लेकर यहां एक धरने में हिस्सा लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान रेड्डी ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राजग सरकार पर सवाल नहीं उठाने के लिए बीआरएस नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा, ''मैं मोदी के खिलाफ लड़ने के बड़े-बड़े दावे करने वाले बीआरएस के नेताओं से पूछ रहा हूं : आपने अब तक क्या किया है? आपने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई?'' उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात की चिंता नहीं है कि बीआरएस का भाजपा में विलय होगा या नहीं, लेकिन केसीआर (के चंद्रशेखर राव) को सेबी मामले में अपने रुख का खुलासा करना चाहिए।

रेड्डी ने पूछा कि बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव इस मुद्दे पर जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं पूछ रहा हूं कि 'ट्विटर किंग' (केटीआर का जिक्र करते हुए) जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यदि भाजपा के साथ कोई समझ नहीं है, तो बीआरएस को जेपीसी (अदाणी मुद्दे की जांच के लिए) की मांग पर अपना रुख प्रकट करना चाहिए।'' तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में अदाणी 'घोटाले' पर जवाब दिए बिना चले गए। उन्होंने कहा कि 2014 तक भारत पर कुल कर्ज का बोझ सिर्फ 55,000 करोड़ रुपए था, लेकिन मोदी के शासनकाल में महज 11 साल में देश पर कर्ज का बोझ बढ़कर 1.15 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के पुराने अभियान की 'टैगलाइन' का जिक्र करते हुए मोदी और अमित शाह (केंद्रीय गृह मंत्री) पर कटाक्ष करते हुए उन्हें 'हम दो, हमारे दो' के रूप में वर्णित किया।

एमएसएमई के प्रति बैंक सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाएं: स्वामीनाथन

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे. ने वित्तीय संस्थानों से एमएसएमई के प्रति अधिक संवेदनशील तथा सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाने और ऋणों के लिए पुनर्गठन विकल्प जैसे सहायक उपाय अपनाने का आह्वान किया, ताकि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस क्षेत्र को समर्थन दिया जा सके।

भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (एफईडीएआई) के वार्षिक दिवस पर यहां आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी गवर्नर ने कहा कि एमएसएमई को किफायती वित्त तक पहुंच, भुगतान में देरी, बुनियादी ढांचे की अड़चनें और अनुपालन की आवश्यकताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के आर्थिक बदलाव की यात्रा एमएसएमई क्षेत्र के मजबूत विकास के बिना पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में कहा, '' एमएसएमई न केवल हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, बल्कि वे वृद्धि, नवाचार तथा रोजगार का भी इंजन है।'' स्वामीनाथन ने कहा कि इन उद्यमों को वास्तव में फलने-फूलने और आगे बढ़ने के लिए वित्तीय क्षेत्र को नवीन समाधान, संवेदनशीलता तथा दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना होगा।

मौजूदा हालात में नीतिगत दर में कटौती का औचित्य भ्रामक: आरबीआई गवर्नर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुंबई/भाषा। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास का मानना है कि 6.5% की मौजूदा नीतिगत दर मोटे तौर पर संतुलित है और इस मोड़ पर नीति में ढील देने का कोई भी औचित्य भ्रामक हो सकता है। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति की बैठक में यह बात कही थी। एमपीसी में रेपो दर पर मतदान के दौरान दो सदस्यों ने दर में कटौती की वकालत की थी।

नीतिगत दर पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च इकाई एमपीसी की पिछली बैठक छह से आठ अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। इस दौरान आरबीआई ने लगातार नौवीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखने की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को एमपीसी की इस बैठक के ब्योरे जारी किए। इसके मुताबिक, मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 2.50 प्रतिशत की वृद्धि और उसके बाद समायोजन वापस लेने के रुख में बदलाव ने 2022-23 में धीरे-धीरे मुद्रास्फीति को कम करने में मदद की है। दास ने कहा था, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.5 प्रतिशत प्रमुख मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के साथ, वर्तमान नीतिगत रेपो दर मोटे तौर पर संतुलन में है और घरेलू आर्थिक गतिविधि के महंगे असर से बचाती है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि जब लक्ष्य की दिशा में टिकाऊ मुद्रास्फीति प्रगति पर है, तो संतुलन-तटस्थ ब्याज दर का मुद्दा समय से पहले है। दास ने कहा, वास्तविक दुनिया में नीति निर्माण एक अमूर्त, सैद्धांतिक और मॉडल-विशिष्ट निर्माण पर आधारित नहीं हो सकता है। इसलिए, तथाकथित उच्च वास्तविक दरों के आधार पर नीति में ढील देने का कोई भी औचित्य भ्रामक हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति धीरे-धीरे कम हो रही है, लेकिन इसकी रफ्तार धीमी और असमान है। खुदरा मुद्रास्फीति का चार प्रतिशत के लक्ष्य के साथ स्थायी तालमेल अभी भी कुछ दूर है।

आंध्र प्रदेश की दवा कंपनी में 'विलायक' का रिसाव होने से आग लगने की आशंका: अधिकारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अचुतापुरम (आंध्र प्रदेश)/भाषा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम के अस्पताल जा कर, अचुतापुरम में एक दवा कंपनी के कारखाने में विलायक (सॉल्वेंट) का रिसाव होने से लगी आग में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। नायडू ने घायलों को सहायता राशि के साथ साथ, इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरतने का आश्वासन दिया।

अचुतापुरम में दवा कंपनी के कारखाने में लगी आग की घटना में 17 लोगों की मौत हुई है। इस बीच, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अचुतापुरम स्थित दवा कंपनी के कारखाने में विलायक (सॉल्वेंट) का रिसाव होने से आग लगने की आशंका है। विलायक (सॉल्वेंट) कोई भी पदार्थ है, आमतौर पर तरल, जो एक या कई पदार्थों को घोलने में सक्षम होता है और एक घोल बनाता है। अनकापल्ली की जिलाधिकारी विजया कृष्णन ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि बुधवार को हुई इस घटना के बाद मृतक संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा, दवा कंपनी के कारखाने में आग लगने के वास्तविक कारण का अभी पता नहीं चल सका है। कृष्णन ने कहा कि घटना की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि एक पाइप से विलायक का रिसाव हुआ जो बिजली के पैनल पर गिरा, जिसके कारण आग लगी। विजया कृष्णन ने कहा कि विलायक (सॉल्वेंट) का रिसाव होने से 'एसेंशिया एडवांस्ड साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के संयंत्र में आग लग गई, जिसके कारण 17 लोगों की मौत हो गई और 33 लोग घायल हो गए। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अस्पताल में उपचाराधीन घायलों से मिलने के बाद कहा कि गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को 50 लाख रुपए तथा अन्य घायलों को 25 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।

पोर्श कार हादसा: चालक किशोर के माता-पिता एवं चार अन्य आरोपियों को नहीं मिली जमानत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पुणे (महाराष्ट्र)/भाषा। पुणे की एक अदालत ने कल्याणी नगर पोर्श कार हादसा प्रकरण में कथित रूप से रक्त नमूने बदले जाने के सिलसिले में किशोर चालक के माता-पिता समेत छह लोगों के जमानत आवेदनों को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू एम मुधोलकर ने 17 वर्षीय किशोर के पिता विशाल अग्रवाल और माता शिवानी अग्रवाल, ससून जनरल अस्पताल के चिकित्सकों-- डॉ. अजय तावडे और डॉ. श्रीहरि हल्नोर तथा कथित बिचौलियों-- अश्पक मकानदार और अमर गायकवाड़ को जमानत देने से इनकार कर दिया।

आरोप है कि 19 मई को तड़के किशोर चालक ने अपनी कार से एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी थी, जिसके फलस्वरूप दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गयी थी। किशोर के माता-पिता एवं अन्य ने यह साबित करने के लिए रक्त नमूने बदलने की साजिश रची थी कि वह कार चलाते समय नशे में नहीं था।

अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि यदि जमानत दी गयी तो आरोपी गवाहों पर दबाव डाल सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

वरिष्ठ सरकारी वकील शिशिर हिरय ने कहा कि उनका मुख्य तर्क यह था कि आरोपियों ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ करके न्यायिक प्रणाली के साथ खिलवाड़ किया।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
बेंगलूरु क्लासीफाइड
उपलब्ध
FLATS FOR SALE
PURVA
BLUBELLE
Adjacent to **Magadi road Metro station**
Rajajinagar Centre of the City
3 bedroom & Exclusive 5 bedroom Flats + servant room with all luxurious Amenities,
Contact : 9844027560

देश की आर्थिक गति बरकरार, 6.5 से 7 प्रतिशत वृद्धि हासिल करने की उम्मीद: वित्त मंत्रालय रिपोर्ट

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। अनियमित मानसून के बावजूद भारत की आर्थिक गति बरकरार है और आर्थिक समीक्षा में 6.5 से 7.0 प्रतिशत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर का अनुमान सही जान पड़ता है। वित्त मंत्रालय की बृहस्पतिवार को जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई।

जुलाई की मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार महीनों में अपनी गति बनाए रखी है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया, चालू वित्त वर्ष 2024-25 के पहले चार (अप्रैल-जुलाई) महीनों में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह कर आधार के विस्तार तथा आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के दम पर मुमकिन हुआ। रिपोर्ट में कहा गया, ''विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के क्रय प्रबंधकों के सूचकांक के मजबूत प्रदर्शन से भी घरेलू गतिविधियों में मजबूती का पता चलता है। विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि का कारण मांग का बढ़ना, नए निर्यात ऑर्डर में तेजी तथा उत्पादन कीमतों का बढ़ना है।''

राजकोषीय मोर्चे पर इसमें कहा गया कि बजट वित्त वर्ष 2024-25 ने राजकोषीय मजबूती का मार्ग प्रशस्त किया है। मजबूत राजस्व संग्रह, राजस्व व्यय में अनुशासन तथा मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के समर्थन से राजकोषीय घाटे में कमी आने का अनुमान है। साथ ही, इसमें कहा गया कि पूंजीगत व्यय को उच्च स्तर पर बनाए रखा गया है, जिससे नए निजी निवेश चक्र को समर्थन मिल रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया, खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2024 में घटकर 3.5 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2019 के बाद सबसे कम है। यह खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी का नतीजा है।

अभिनेता से राजनेता बने विजय ने अपनी पार्टी का ध्वज जारी किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। लोकप्रिय तमिल फिल्म अभिनेता से राजनेता बने विजय ने बृहस्पतिवार को अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिझगा वेत्री कषगम' (टीवीके) का ध्वज जारी किया और यहां नजदीक में ही पनायूर स्थित अपने पार्टी मुख्यालय में इसे फहराया। यह ध्वज दो रंगों का है, इसमें ऊपर और नीचे मरून रंग तथा बीच में पीला रंग है, जिसके मध्य में वागई फूल के दोनों ओर दो लड़ते हुए हाथियों की आकृति बनी हुई है।

'वागई' फूल को अल्बिजिया लेबेक के नाम से भी जाना जाता है। तमिल में 'वागाई' शब्द का अर्थ 'विजय' होता है। ध्वज के अनावरण और पार्टी गान को आधिकारिक रूप से जारी किये जाने के साथ टीवीके का प्रवेश तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह पार्टी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए कमर कस रही है। हालांकि, विजय ने फरवरी में ही अपने राजनीतिक संगठन के शुभारंभ की घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया और न ही चुनाव के दौरान किसी पार्टी का समर्थन किया। टीवीके का ध्वज फहराते हुए अभिनेता ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संकल्प लिया। संकल्प में कहा गया है, हम हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले और अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों की सदैव सराहना करेंगे तथा तमिल भूमि के हमारे लोगों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष करने वाले अनगिनत सैनिकों की भी सराहना करेंगे। पार्टी ने जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर भेदभाव को दूर करने और लोगों में जागरूकता पैदा करने तथा सभी के लिए समान अवसर एवं अधिकार के लिए प्रयास करने का संकल्प लिया।

विजय ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, पार्टी के झंडे के पीछे ऐतिहासिक महत्व की एक दिलचस्प कहानी है। मैं आगामी राज्य-स्तरीय सम्मेलन में पार्टी के सिद्धांतों और कार्ययोजना के साथ-साथ इस बारे में भी बताऊंगा। उन्होंने कहा, यह महज एक पार्टी का झंडा नहीं है। मैं इसे तमिलनाडु की भावी पीढ़ियों की जीत के झंडे के रूप में देखता हूं। इस अवसर पर उनके माता-पिता, फिल्म निर्देशक एस. ए. चंद्रशेखर और शोभा चंद्रशेखर भी मौजूद थे। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी वर्षों में कड़ी मेहनत करने और लोगों के उत्थान का आह्वान किया। टीवीके के पहले राज्य-स्तरीय सम्मेलन की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

तमिलनाडु सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं: स्टालिन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने अपने मंत्रिमंडल में बृहस्पतिवार को किये जाने वाले संभावित फेरबदल की जोरदार चर्चा के बीच कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से उनके मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल के बारे में प्राप्त कुछ सूचना के बारे में पूछा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है।

मीडिया में बृहस्पतिवार को चर्चा थी कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए अगले सप्ताह मुख्यमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सकता है, जिसमें कुछ नामों को हटाया जा सकता है और कुछ नए लोगों को शामिल किया जा सकता है।

स्टालिन के बेटे और युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री उदयनिधि को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना की भी चर्चा हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि इस कदम के लिए अभी सही समय नहीं आया है। राज्य में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उदयनिधि को मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) में आवाज उठ रही है। इसके पहले केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन ने अपने बयान में कहा था कि हाल ही में द्रमुक के दिवंगत अध्यक्ष एम. करुणानिधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में सिक्का जारी करने के लिए आयोजित समारोह का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। मुरुगन के इस दावे पर स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु सरकार ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था जो केंद्र सरकार के नियंत्रण में था। अपनी अमेरिकी यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि विभिन्न बैठकें निर्धारित हैं और बैठकों के नतीजे बाद में मीडिया को बताए जाएंगे।

कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमे की अनुमति पर फैसले के लिए राज्यपाल को 'सलाह' देंगे : कर्नाटक मंत्रिमंडल

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने जनता दल (सेक्युलर) नेता एवं केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी तथा खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी सहित भाजपा के तीन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर निर्णय के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को 'सहायता और सलाह' देने का बृहस्पतिवार को फैसला किया।

कांग्रेस सरकार ने यह कदम मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि आवंटन 'घोटाले' में 16 अगस्त को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के एक सप्ताह के भीतर उठाया है। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, लंबित मामलों में जल्द से जल्द निर्णय लेने तथा न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत मंत्रिमंडल राज्यपाल को सहायता एवं सलाह दे सकता है। इसका उपयोग करते हुए मंत्रिमंडल ने राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने को अपनी मंजूरी दी है।

पाटिल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को फैसलों की जानकारी देते हुए बताया, सलाह राज्यपाल को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा, जिन चार लंबित मामलों में हमने सहायता और सलाह दी है, इनमें से दो मामलों (जनार्दन रेड्डी और कुमारस्वामी) में आरोप-पत्र दायर किये जा चुके हैं...।

पाटिल से जब यह पूछा गया कि क्या राज्यपाल मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह को अस्वीकार कर सकते हैं, उन्होंने कहा, हमारे अनुसार, वह हमारी सलाह मानने को बाध्य हैं; उनका विवेकाधिकार सीमित है। मुझे यकीन है कि वह अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल बहुत विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे।

राज्यपाल ने 16 अगस्त को सिद्दरामय्या के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत एस पी प्रदीप कुमार, टी जे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा की याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। पाटिल ने कहा कि अभियोजन की मंजूरी मांगने वाली कई अर्जी राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं, जिनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाएं भी शामिल हैं; इनमें से कुछ मामलों में आरोप-पत्र भी दायर किये जा चुके हैं।

मंत्री ने कहा कि इन अर्जियों में से विशेष अर्जी (भाजपा की पूर्व मंत्री) शशिकला जोले के विरुद्ध हैं, जिनके खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने नौ दिसंबर, 2021 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि (भाजपा के पूर्व मंत्री) मुरुगेश निरानी के खिलाफ इसी कानून की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन के लिए 26 फरवरी, 2024 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने बताया कि तीसरी अर्जी कुमारस्वामी मामले को लेकर है, जिनके खिलाफ 21 नवंबर 2023 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। अर्जी में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 और भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम (बीएनएसएस) के प्रावधानों के तहत मंजूरी मांगी गई है। पाटिल ने कहा कि विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोप-पत्र दाखिल कर दिया है और राज्यपाल ने 29 जुलाई, 2024 को मामले पर स्पष्टीकरण मांगा था, जिसपर इसने (एसआईटी ने) 16 अगस्त, 2024 को आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया है।

उन्होंने बताया कि चौथा मामला रेड्डी से संबंधित है, जिनके खिलाफ 13 मई, 2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 और बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत मंजूरी मांगने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और इस मामले में आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। मंत्री ने कहा कि राज्यपाल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब जांच एजेंसियों ने दे दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जनता की नजर में राज्यपाल का कार्यालय गलत काम करता हुआ नहीं दिखना चाहिए; इसलिए हमें लगा कि यह सहायता और सलाह देना उचित है। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्दरामय्या के मामले में एक निजी व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि इन चार मामलों में जांच हो चुकी है और दो मामलों में आरोप-पत्र दाखिल किए जा चुके हैं।

दक्षिण भारत का अपना पहला संयंत्र तमिलनाडु में स्थापित करेगी डाबर : मंत्री राजा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई/नयी दिल्ली। दैनिक उपयोग की घरेलू वस्तुएं बनाने वाली कंपनी डाबर इंडिया तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में 400 करोड़ रुपये की लागत से एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। दक्षिण भारत में यह उसकी पहली इकाई होगी। डाबर इंडिया ने बयान में कहा, समझौता ज्ञापन में प्रथम चरण के लिए 135 करोड़ रुपये के स्वीकृत निवेश की रूपरेखा दी गई है, जिसे पांच वर्षों में बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया जाएगा।

तमिलनाडु के विलुप्पुरम जिले में एसआईपीसीओटी तिंडीवनम में स्थापित नए संयंत्र से डाबर को दक्षिण भारत से अपने कारोबार को और बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसकी वर्तमान में उसके घरेलू कारोबार में करीब 18-20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, उद्योग मंत्री टी.आर.बी. राजा, मुख्य सचिव एन मुरुगनंदम की उपस्थिति में राज्य की निवेश प्रोत्साहन एजेंसी 'गाइडेंस तमिलनाडु' के प्रबंध निदेशक विष्णु और डाबर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मोहित मल्होत्रा ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

राजा ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा, डाबर इंडिया तमिलनाडु में आपका स्वागत है। बल्कि दक्षिण भारत में आपका स्वागत है। राज्य के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की उपस्थिति में आज गाइडेंस तमिलनाडु ने विल्लुपुरम जिले के तिंडीवनम में एसआईपीसीओटी फूड पार्क में डाबर के साथ दक्षिण भारत में उसका पहला विश्व स्तरीय विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने कहा कि कंपनी इस सुविधा में 400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे 250 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा। राजा ने कहा, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे आस-पास के डेल्टा क्षेत्र के किसानों के लिए कृषि उत्पाद बेचने के नए अवसर खुलेंगे..।

डाबर इंडिया के सीईओ मोहित मल्होत्रा ने कहा, इस निवेश से हम दक्षिण भारत में अपने उत्पादों की बढ़ती मांग को बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। इस क्षेत्र में अपनी बाजार उपस्थिति को मजबूत कर सकेंगे। हम नौकरियां सृजन कर और स्थानीय विक्रेताओं तथा आपूर्तिकर्ता भागीदारों के साथ मिलकर काम कर तमिलनाडु के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए तत्पर हैं। डाबर इंडिया के निदेशक मंडल ने दक्षिण भारत में एक नई सुविधा स्थापित करने के लिए 135 करोड़ रुपये के निवेश को 31 जनवरी को मंजूरी दी थी।

हमें अपना बुनियादी ढांचा विकसित करने की आवश्यकता : जोशी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत प्रतिभा, जनशक्ति और क्षमता से भरपूर है, इसलिए हमें आगे बढ़ने तथा देश में और अधिक विनिर्माण करने की आवश्यकता है।

जोशी यहां राष्ट्रीय परीक्षण शाला (एनटीएच) में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखने के लिए बेंगलुरु में थे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे जोशी ने कार्यक्रम में कहा, प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना बहुत जरूरी है। हमें अपनी प्रणाली, अपना बुनियादी ढांचा विकसित करने की जरूरत है। इस दिशा में, मेरे गृह राज्य में पहली ईवी बैटरी परीक्षण सुविधा खोली जाएगी।

उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार का प्रत्येक निर्णय आपस में जुड़ा हुआ है और यह 'आत्मनिर्भरता' की दिशा में एक कदम है। जोशी ने कहा, उदाहरण के लिए, हमारी योजना 2030 तक भारतीय सड़कों पर 30 प्रतिशत ईवी वाहन लाने की है। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि ईवी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बिजली नवीकरणीय हो, इसलिए हम बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं। हम एक करोड़ घरों में निःशुल्क सौर ऊर्जा इकाई लगाने पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमें नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंच मिल सके। उन्होंने एनटीएच से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करके तथा ईवी परीक्षण जैसी अधिक सुविधाएं स्थापित करके अपनी परीक्षण क्षमता में विविधता लाने का भी आग्रह किया।

एनटीएच विभिन्न क्षेत्रों में परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में अग्रणी रहा है। यह उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन कार्य करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे हर संभव सहायता प्रदान करेगी। एनटीएच को पहले ही भारत में सेंट्रल विस्टा और मेट्रो रेल जैसी कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाएं मिल चुकी हैं। इसलिए, इसे तीन साल में 100 करोड़ रुपये की कंपनी बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। मंत्री ने कहा कि बेंगलुरु के अलावा, सरकार की मुंबई और कोलकाता में भी ईवी परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की योजना है।

उपमुख्यमंत्री शिवकुमार आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

बेंगलूरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले की जांच के सिलसिले में बृहस्पतिवार को लोकायुक्त पुलिस के समक्ष पेश हुए। कांग्रेस सरकार द्वारा उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दी गई सहमति 23 नवंबर 2023 को वापस लेने और मामले को लोकायुक्त पुलिस के पास भेजने के बाद उसने फरवरी में शिवकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

लोकायुक्त के समक्ष पेश होने के बाद शिवकुमार ने संवाददाताओं से कहा, लोकायुक्त ने कल समन जारी किया था, मैं उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि मैं अलमट्टी के दौरे पर था। इसलिए मैंने आज पेश होने के लिए अनुरोध किया था और उन्होंने मुझे आज का समय दिया। लगभग तीन घंटे तक उन्होंने मुझसे पूछताछ की। मैंने उन्हें जवाब दे दिए हैं। उन्होंने और दस्तावेज मांगे हैं, मैं उन्हें जमा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि तथ्यों का अध्ययन करने के बाद, लोकायुक्त एक बार फिर उन्हें पेश होने का नोटिस जारी करेंगे।

शिवकुमार ने कहा, एक बात जरूर है कि सीबीआई उनसे (लोकायुक्त से) बेहतर है। उन्होंने मुझसे अलग-अलग चीजों पर कई सारे सवाल पूछे। सीबीआई ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं पूछा है, उसने मुझे अभी तक नहीं बुलाया है। लेकिन उन्होंने (लोकायुक्त) मुझे बुलाया है और मुझे परेशान कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मामले को सीबीआई से लोकायुक्त को सौंपने के बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा कि लोकायुक्त पिछले छह माह से मामले की जांच कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, सीबीआई को जांच रोक देनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वे मेरे सभी लोगों को परेशान कर रहे हैं। उसने मुझे अभी तक तलब नहीं किया है, लेकिन वे मेरे कई मित्रों और रिश्तेदारों को परेशान कर रहे हैं। अब इन लोगों (लोकायुक्त) ने भी उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिवकुमार के खिलाफ दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को 15 जुलाई को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एससी शर्मा की उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा था कि वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

शीर्ष अदालत शिवकुमार द्वारा 19 अक्टूबर 2023 के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच पूरी करने और तीन माह के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। वह इस अवधि के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।

केरल सरकार हेमा समिति की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करे : उच्च न्यायालय

कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़ी हेमा समिति की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति एस. मनु की पीठ ने यह निर्देश तिरुवनंतपुरम निवासी नवास द्वारा दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में दावा किया गया है कि रिपोर्ट में गंभीर आरोप हैं। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सरकार से पूछा कि हेमा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उसकी अगली कार्रवाई क्या होगी। इस पर सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील दी कि जब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराता, तब तक मामला दर्ज करना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने कहा कि उसके पास बिना सेंसर की गई मूल रिपोर्ट में उल्लिखित सभी नाम हैं, जो एक गोपनीय दस्तावेज है।

इसमें कहा गया कि समिति को फिल्म उद्योग में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने का काम सौंपा गया था, लेकिन सरकार के पास मामले दर्ज करने की सीमाएं हैं क्योंकि समिति द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित करने के बाद बयान दर्ज किए गए थे। सरकार ने कहा कि गोपनीयता संबंधी बयान के मद्देनजर मामला दर्ज करना संभव नहीं है। अधिवक्ता ने कहा कि अगर कोई आगे आकर शिकायत दर्ज कराएगा तो मामला दर्ज किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को इस मामले में राज्य महिला आयोग को भी पक्षकार बनाया। जनहित याचिका में मूल रिपोर्ट सार्वजनिक करने का अनुरोध किया गया है तथा उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह राज्य सरकार को रिपोर्ट में उल्लिखित कथित यौन अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दे। न्यायमूर्ति के. हेमा समिति का गठन 2017 में अभिनेता दिलीप से जुड़े अभिनेत्री हमला मामले के बाद मलयालम सिनेमा में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2019 में जमा की थी, लेकिन सरकार ने विवरण जारी नहीं किया क्योंकि इसमें संवेदनशील जानकारी होने का संदेह था।

कांग्रेस ने केरल सरकार से हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने को कहा

तिरुवनंतपुरम/कोच्चि। कांग्रेस ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार पर हेमा समिति की रिपोर्ट के संबंध में बृहस्पतिवार को केरल सरकार से कड़ी कार्रवाई करने को कहा। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) अध्यक्ष के. सुधाकरन ने संवाददाताओं से कहा कि अगर 2026 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुधाकरन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि समिति की जिस रिपोर्ट में महिलाओं और यहां तक कि नाबालिग लड़कियों के साथ विभिन्न अत्याचारों के संबंध में गंभीर जानकारी दी गई है उसे वर्षों तक रोक कर रखा गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को इतने लंबे समय तक लटकाए रखने का निर्णय उचित नहीं ठहराया जा सकता। सुधाकरन ने कहा, कांग्रेस हेमा समिति की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की मांग करती है। विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने दावा किया कि न्यायमूर्ति हेमा ने राज्य सरकार से रिपोर्ट जारी न करने के लिए कभी नहीं कहा।

सतीशन ने उनके द्वारा पहले भी लगाए गए आरोपों को दोहराया और सरकार पर शिकारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सतीशन ने कोच्चि में संवाददाताओं से कहा, हेमा समिति ने सरकार से रिपोर्ट जारी न करने को कभी नहीं कहा, बल्कि उसने इसे जारी कर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों के नामों का खुलासा न करने का निर्देश दिया है और उसका निर्देश रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के खिलाफ नहीं है। सतीशन ने आरोप लगाया कि सरकार अपराधियों को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रुख स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अगर कोई शिकायत देता है तो मामला दर्ज किया जा सकता है। सतीशन ने कहा, प्रस्तावित सिनेमा सम्मेलन में आरोपी भी पीड़िताओं के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। सिनेमा सम्मेलन नारीत्व का अपमान होगा। सतीशन ने राज्य सरकार द्वारा फिल्म उद्योग के मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय सिनेमा सम्मेलन का जिक्र करते हुए यह बात कही।

निवेशकों को राज्य सरकार करेगी पूरा सहयोग : शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में शुरू हो रहे उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा यह राज्य की आर्थिक प्रगति में भी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9-11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाले 'राइजिंग राजस्थान' इन्वेस्टमेंट समिट में निवेशकों को आमंत्रित भी किया।

शर्मा गुरूवार को महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का आज कन्स्ट्रक्शन, अर्थमूविंग, यूटिलिटी एवं लिफ्टिंग, कृषि, वानिकी, खनन जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। ऐसे में देश-विदेश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह संयंत्र उपयोगी साबित होगा। साथ ही, उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संयंत्र का आगे विस्तार भी किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार नवाचारों तथा नई नीतियों के माध्यम से राजस्थान को निवेशकों की पसंदीदा जगह बनाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश में नई औद्योगिक नीति-2024, एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति, राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट पॉलिसी, राजस्थान वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसी विभिन्न नई नीतियों से निर्यात, लॉजिस्टिक इको सिस्टम बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में औद्योगिक गति देने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी पांच वर्ष में 53 हजार किलोमीटर लंबा सड़क नेटवर्क, 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनने जैसे अहम निर्णयों से उद्योगों को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार द्वारा उद्योगों में कुशल मानव संसाधन के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी, अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सलेरेटर तथा नए आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाएंगे जिससे बड़ी संख्या में युवाओं में कौशल विकास संभव होगा। साथ ही, उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर उद्योगपतियों को निवेश संबंधी सभी कार्य एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा इस वर्ष प्रदेश में पानी तथा बिजली की उपलब्धता के लिए निरंतर अहम निर्णय किए जा रहे हैं। जहां बिजली क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ के एमओयू किए गए हैं वहीं पानी के लिए ईआरसीपी, यमुना जल समझौता, देवास परियोजना जैसे निर्णय किए गए, जिससे उद्योगों को उनकी मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में बिजली तथा पानी मिल सके। उन्होंने उद्योपतियों का आह्वान किया कि वे प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करें। सरकार बिजली, पानी, जमीन सहित हर क्षेत्र में उनकी मदद करेगी, जिससे विकसित राजस्थान की संकल्प सिद्धि हो सके।

मुख्यमंत्री ने अजीम प्रेमजी का जयपुर में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट की शुरूआत करने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि अजीम प्रेमजी ने विप्रो का 53 वर्ष तक नेतृत्व किया है तभी विप्रो आज इस मुकाम तक पहुंची है। एक कॉर्पोरेट समूह के रूप में विप्रो की देश-दुनिया में प्रतिष्ठा है। आईटी, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में यह दिग्गज कंपनी मानी जाती है। साथ ही, प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतरीन काम कर रहा है।

विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने कहा कि हाइड्रोलिक प्लांट की स्थापना के लिए उत्तर भारत में सर्वाधिक उपयुक्त जगह हमें राजस्थान लगा तथा भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी हमें पूरा सहयोग दिया। सरकार द्वारा समयबद्ध सुविधाएं उपलब्ध होने से कम समय में ही यह प्लांट बनकर तैयार हो गया।

उन्होंने कहा कि अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के तहत राजस्थान में शिक्षा गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं तथा आगे भी यह कार्य निरंतर जारी रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हाइड्रोलिक प्लांट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक कैलाश वर्मा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, जेसीबी इंडिया लिमिटेड के सीईओ दीपक शेट्टी, विप्रो हाइड्रोक्यूलिस अध्यक्ष सीताराम गणेशन सहित विप्रो कंपनी के पदाधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

राज्यसभा उपचुनाव : निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन रद्द

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव हेतु दाखिल नामांकन पत्रों की जांच में एक निर्दलीय उम्मीदवार का पर्चा रद्द कर दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके साथ ही राज्य से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार व केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का चुना जाना लगभग तय हो गया है। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 27 अगस्त है। अधिकारियों ने बताया कि राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव हेतु तीन प्रत्याशियों द्वारा भरे गये सभी छह नामांकन पत्रों की बृहस्पतिवार को विधानसभा में जांच की गयी। उन्होंने बताया कि इनमें दो प्रत्याशियों के पांच नामांकन पत्र सही पाए गये जबकि एक प्रत्याशी के नामांकन पत्र को रद्द किया गया।

निर्वाचन अधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने भाजपा उम्मीदवार रवनीत सिंह के चार नामांकन पत्रों, भाजपा से प्रतिस्थापन उम्मीदवार के रूप में सुनील कोठारी के एक नामांकन पत्र सही पाए। वहीं जांच में निर्दलीय बबीता वाधवानी का नामांकन पत्र रद्द किया गया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार 27 अगस्त को अपराह्न तीन बजे तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं।

राजस्थान से कांग्रेस के के. सी. वेणुगोपाल के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद इस्तीफा देने से खाली हुई इस सीट पर चुनाव होना है। इस सीट पर सदस्यता का कार्यकाल 21 जून 2026 तक रहेगा केंद्रीय राज्य मंत्री बिट्टू ने बुधवार को नामांकन पत्र दाखिल किया था।

बैंकिंग पहुंच बढ़ाकर विकसित भारत संकल्प को करें साकार : निर्मला सीतारमन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केंद्रीय वित्त एवं सहकारिता मामलात मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को उदयपुर पहुंचीं। वित्त मंत्री ने होटल लीला पैलेस में पश्चिम व मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक ली। वहीं अपराह्न बाद एयरपोर्ट रोड़ स्थित स्मॉल इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बैंक कार्यालय का निरीक्षण किया। वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमन के डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रशासनिक एवं बैंकिंग अधिकारियों ने अगवानी की। वहां से वे पिछोला स्थित होटल लीला पैलेस पहुंची। होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिम-मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के चेयरमैन और उनके प्रायोजित बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र में आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने पर चर्चा की गई। बैंकों की पिछले वित्तीय वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना एवं प्रगति की समीक्षा की गई। केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग पहुंच बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से आमजन को लाभ देने के लिए बैंक के सभी अधिकारी समन्वय से कार्य करें।

बैठक में वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव श्री एम नागराजू, अपर सचिव एमपी तंगीराला सहित नाबार्ड के चेयरमैन के बी शॉ, आरबीआई के कार्यपालक निदेशक जयंत कुमार दास, बैंक ऑफ़ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी देवदत्त चाँद, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक निधू सक्सेना, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी ने अपने-अपने बैंकों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। साथ ही बैंकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। बैठक में नाबार्ड, सिडबी, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ़ इंडिया के नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों के साथ ही पश्चिम मध्य क्षेत्र के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के अध्यक्षों ने भाग लेकर अपने-अपने बैंकों की प्रगति रिपोर्ट और आगामी कार्ययोजना से केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया।

डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर किए तीखे हमले, बोले काम कर लो, नहीं तो अपने ही कुर्सी से हटा देंगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। कांग्रेस ने अडानी मामले में जेपीसी जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने जयपुर में ईडी कार्यालय के बाहर धरना व प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बीजेपी और मुख्यमंत्री भजनलाल पर किए गए तीखे हमलों ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। डोटासरा ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री को सुधारने की सलाह दी है, अन्यथा चेतावनी दी कि उनके अपने ही लोग उन्हें कुर्सी से हटा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे भी चुप नहीं रहेंगी और कुछ न कुछ जरूर कर रही होंगी। डोटासरा ने भजनलाल को चेताया कि मुरली वाला भगवान उनकी मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें खुद भी काम करना पड़ेगा।

डोटासरा ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे जनता की समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बारिश में किस तरह लोग परेशान हुए, स्टूडेंट, किसान सब परेशान हैं। काम करना पड़ेगा। सिर्फ घूमने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की कि वे राजस्थान के 8 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं।

डोटासरा ने भाजपा पर भी हमला बोला, कहा कि उनकी पार्टी में जनता की समस्याओं को सुनने का कोई नहीं है। मंत्री विधायक खुद बोल रहे हैं वे किसी का काम नहीं करवा सकते हैं। राज्य के सभी बड़े कार्यों के ठेके गुजरात के लोगों को दिए जा रहे हैं। डोटासरा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को 9 माह होने वाले हैं और इसमें खूब भ्रष्टाचार हुए हैं। इनकी फाइलें हमारे पास आ रही है। विधानसभा में इन घोटालों को पूरी ताकत के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मुखर होकर आवाज उठाएगी। इस पूरे प्रकरण से यह साफ है कि राजस्थान की राजनीति में गहरे उथल-पुथल का दौर शुरू हो चुका है, और आने वाले समय में यह और भी तीव्र हो सकता है।

राजस्थान के कोटा व अजमेर सहित चार जिलों में भारी बारिश

जयपुर। राजस्थान में बारिश का दौर जारी है जहां बीते चौबीस घंटे में कोटा व अजमेर सहित चार जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, बृहस्पतिवार को सुबह साढ़े आठ बजे तक बीते 24 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं पर तथा पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर बादलों की गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है।

इस दौरान राजसमन्द, बारां, कोटा तथा अजमेर जिले में कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई है। सर्वाधिक 89 मिलीमीटर बारिश अजमेर के नसीराबाद में हुई। इसी तरह राजसमंद जिले के खमनोर में 77 मिमी., नाथद्वारा में 68 मिमी., कोटा के देवगढ़ में 67 मिमी. और बारां में 65 मिमी. बारिश हुई। उदयपुर, टोंक, सिरोही, करौली, जोधपुर, डूंगरगढ व चित्तौड़गढ़ जिले में भी कई जगह अच्छी खासा बारिश हुई। एक नए मौसमी तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना है।

देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पंजाब के किसान भाजपा से नाराज हैं : बिट्टू

जयपुर। राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने बुधवार को कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पंजाब के किसान भाजपा से नाराज हैं। बिट्टू ने कहा कि पंजाब के किसान भाजपा से खुश हैं, लेकिन चंद किसान नेता अपना पेट भरने और किसानों को गुमराह करने के लिए यह दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पहले हरियाणा और फिर 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर अपनी सरकार बनाएगी।

बिट्टू ने यहां संवाददाताओं से कहा, देश में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि पंजाब के किसान भाजपा से नाराज हैं। पंजाब के किसान भाजपा से खुश हैं, लेकिन चंद किसान नेता अपना पेट भरने और किसानों को गुमराह करने के लिए यह दुष्प्रचार कर रहे हैं। राज्य में तीन सितंबर को राज्यसभा सीट के लिये चुनाव होने हैं। राजस्थान में राज्यसभा की कुल 10 सीट हैं और उनमें से एक खाली है। भाजपा के पास चार और कांग्रेस के पास पांच सीटें हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले किसान नेता कहते थे कि उन्हें दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा, लेकिन वे संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से आकर मिले।

साथिनों को ग्राम पंचायतों में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को दिया जाएगा आदेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। महिला अधिकारिता निदेशालय एवं पंचायती राज विभाग द्वारा मंजरी संस्थान की भागीदारी में यूनीसेफ राजस्थान के तकनीकी व वित्तीय सहयोग से 'पंचायत संग साथिन' (राष्ट्रीय ग्राम स्वराज) अभियान के अंतर्गत सरपंच एवं साथिनों के लिए बाल एवं महिला हितैषी पंचायत विषय पर 22 और 23 अगस्त 2024 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न सत्रों में चर्चा की जाएगी। पंचायती राज आयुक्त एवं शासन सचिव रवि जैन ने प्रशिक्षण कार्यशाला की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरपंच और साथिन मिलकर काम करें जिससे ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उनके सम्पूर्ण विकास के लिए साथिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत आवश्यक है कि साथिनों को ग्राम पंचायतों में बैठने का स्थान मिले। इसके लिए पंचायती राज विभाग की ओर से ग्राम पंचायतों को जल्दी ही आदेश जारी कर पाबंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला उत्थान में साथिनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पंचायती राज विभाग और महिला बाल विकास विभाग द्वारा साथिनों के कैडर को मजबूत करने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साथिन हर महीने आयोजित होने वाली महिला शक्ति समूहों की बैठक आयोजित करें और इसकी रिपोर्ट भी नियमित रूप से भिजवाएं।

महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव डॉ. मोहनलाल यादव ने प्रतिभागियों की प्रशिक्षण के संदर्भ में अपेक्षाओं के बारे में बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर महिला विकास के कार्यों में साथिनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि साथिनों को अपनी वर्तमान और प्रस्तावित भूमिकाओं के प्रभावी निर्वहन में सक्षम बनाने के लिए पूर्व निर्धारित अंतराल पर आधारभूत और अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता बनी रहती है।

सरकार स्वच्छता के प्रति कटिबद्ध : मदन दिलावर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि राजस्थान सरकार स्वच्छता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए हम सभी को मिलकर सहयोग करना होगा। दिलावर गुरुवार को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से सफाईकर्मियों की सुरक्षा, समानता एवं सम्मान पर कार्य करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयासों के लिए आयोजित कार्यशाला में उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता का काम चुनौतीपूर्ण है। पूर्व में गाँव-शहर में गंदगी रहने से स्वच्छता का अभाव था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सड़कों पर उतरकर स्वच्छता का कार्य हाथ में लिया तब से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हम सभी का कर्तव्य है कि धरती माता को और भी स्वच्छ रखना चाहिए। इसका चप्पा-चप्पा स्वच्छ रहना चाहिए। हमें भारत माता को हर हाल में श्रृंगारित करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले दो-तीन वर्षों में स्वच्छता की दृष्टि से राजस्थान हिंदुस्तान में प्रथम स्थान पर आये। इसके लिए सभी को अपना आदर्श प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान को स्वस्थ एवं स्वच्छ बनाने के लिए विशेषज्ञों से भी सलाह मशविरा किया जाय।

सफाईकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा कि इन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध करवाए जाय।उपकरणों के उपयोग के बारे में इन्हें प्रशिक्षण दिया जाय। राजस्थान सरकार ने बीएसआर की रेट तय की है। इससे काफी लोगों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू

सड़क हादसे में गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर राज्य सरकार देगी 10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में राज्य में मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर को कम करना है। प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय (गोल्डन ऑवर) में राज्य के निकटतम सरकारी एवं निजी चिकित्सा संस्थान (अस्पताल/ट्रोमा सेंटर आदि) पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को राज्य सरकार 10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र देगी। इसके लिये मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना का गठन किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने घायल व्यक्तियों के जीवन रक्षा के परिप्रेक्ष्य में घायल व्यक्ति को न्यूनतम समय में चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने की दृष्टि से आमजन को प्रेरित करने के उद्देश्य से 21 अगस्त, 2024 को दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना के लिए बजट परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन किया जाएगा। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाला भला व्यक्ति स्वेच्छानुसार अपनी पहचान आदि देने तथा योजना का लाभ लेने को तैयार होने पर अस्पताल के इमरजेंसी रूम में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर द्वारा भले व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, बैंक डिटेल इत्यादि की जानकारी फॉर्म में दी जाएगी। मेडिकल ऑफिसर के अतिरिक्त संबंधित थानाधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भी भले व्यक्ति को इस योजना का लाभ दिलाने की अनुशंसा निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं को दुर्घटना के 3 दिवस के अंदर की जाएगी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को निकटतम राजकीय अथवा निजी अस्पताल में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने एवं उसकी इच्छानुसार तत्काल अस्पताल से जाने की अनुमति होगी। यदि घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का है तो उसकी मदद करने वाले वाले भले व्यक्ति को 10 हजार रूपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा।

जन्माष्टमी पर श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए : गुर्जर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। राजधानी जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां का दौर शुरू हो चुका है। इस दिन लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ पहुंचेंगे। मंदिर कमेटी के साथ-साथ जयपुर नगर निगम हेरिटेज ने भी सफाई और अन्य व्यवस्थाओं का काम संभाल लिया है। हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने गुरुवार को गोविंद देव जी मंदिर पहुंचकर गोविंद देव जी के दर्शन किए और महंत मानस गोस्वामी से मंदिर को लेकर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के अधिकारी भी रहे। महापौर ने सफाई और रोशनी की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को आदेश दिया कि जन्माष्टमी पर किसी भी तरह की श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होनी चाहिए। गोविंद देव जी मंदिर से लेकर गोपीनाथ जी मंदिर तक पहुंची। यहां रास्ते में लोगों ने उन्हें समस्या बताई। उन्होंने अधिकारियों से साफ-सफाई करने नालियों की सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही रोड लाइटों को सही करने की निर्देश दिए। मुनेश गुर्जर ने बड़ी चौपड़, बापू बाजार ,चौड़ा रास्ता, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ होते हुए गोपीनाथ जी मंदिर तक का दौरा किया।

इस दौरान गोपीनाथ जी की मंदिर के महंत से मुलाकात की। उनसे भी पूछताछ की जानकारी ली और समस्या निस्तारण का भरोसा दिलाया। मंदिर के महंत ने उन्हें प्रसादी भेंट किया और तस्वीर भी भेंट की। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव है तो ऐसे में सबसे ज्यादा भीड़ गोविंद देव जी के मंदिर में ही होनी है। इसलिए पूरे प्रशासन का ध्यान भी गोविंद देव जी मंदिर और आसपास के इलाकों पर है, जिससे आने जाने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो।

अगले दो साल में दो लाख नौजवानों को देंगे सरकारी नौकरी : योगी आदित्यनाथ

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मुजफ्फरनगर/लखनऊ/भाषा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार अगले दो साल में दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि पहले नौकरियां निकलती थीं तो पश्चिमी उप्र के युवाओं को उससे वंचित रखा जाता था, लेकिन आज यहां के युवा और बेटियां नौकरियां प्राप्त कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शुक्रवार से प्रदेश में 60 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है। योगी ने कहा, '' प्रदेश में निकलने वाली सरकारी नौकरियों में पश्चिमी उप्र के युवाओं को बढ़चढ़ कर भाग लेना होगा। कोई माई का लाल युवाओं की योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा कर पाएगा।'' उन्होंने आगाह किया कि किसी ने भी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसे जेल भेजने के साथ ही उसकी संपत्तियों को जब्त करके गरीबों में बांट दिया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को यहां बीआईटी कॉलेज में आयोजित जनपद स्तरीय वृहद रोजगार एवं ऋण मेला में शामिल हुए। इस दौरान पांच हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। साथ ही

विभिन्न योजनाओं में चयनित पात्रों एवं एमएसएमई उद्यमियों में 30 करोड़ रुपए का ऋण भी वितरित किया गया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत एक हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को टैबलेट भी वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के जनपदों में हर तीन माह में रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को नमन करते हुए कहा, '' मुजफ्फरनगर को सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिल रही है। खासकर मीरापुर विधानसभा क्षेत्र को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिलने जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर वही स्थान है, जो 10 साल पहले दंगों की आग में झुलसता था, आज ये दंगामुक्त हो चुका है और यहां धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरनगर की नई पहचान विकास, सुरक्षा, नौजवानों को काम, सरकारी नौकरी के रूप में बन रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ''उन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि उनके उस बॉन्ड का क्या हुआ, जिसे एक लाख रुपए देने के लिए भरवाया गया था।''

राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद-370 बहाल करना चाहते हैं : गिरिराज सिंह

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बृहस्पतिवार को दावा किया कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि इस कदम को देश स्वीकार नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने श्रीनगर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन की प्राथमिकता है।

राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस दिलाना है। केंद्र ने 2019 में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था और तत्कालीन राज्य को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था। कपड़ा मंत्री सिंह ने यहां दिल्ली हाट में 'शिल्प दीदी महोत्सव' से इतर पीटीआई-भाषा के साथ बातचीत में कहा, ''यह राहुल गांधी के दिमाग में है। वह कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा।'' भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नेता ने राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता तब से थके हुए लग रहे हैं जब से उनसे उनके 'धर्म और जाति' के बारे में पूछा गया है।

झारखंड : प्रशिक्षु पायलट और प्रशिक्षक का शव मिला, लापता विमान की तलाश जारी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जमशेदपुर/भाषा। झारखंड के जमशेदपुर स्थित हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हुए दो सीट वाले विमान में सवार प्रशिक्षु पायलट और प्रशिक्षण देने वाले पायलट का शव बृहस्पतिवार को चांडिल बांध में पाया गया जबकि विमान की तलाश जारी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि एक निजी उड़ान प्रशिक्षण संस्थान 'अलकेमिस्ट एविएशन' का विमान 'सेसना 152' मंगलवार सुबह सोनारी हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था, जिसके बाद बांध के जलाशय सहित आस-पास के इलाकों में इसका पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर खोजबीन अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि विमान के चांडिल बांध के आस-पास दुर्घटनाग्रस्त होने का संदेह था।

अधिकारियों ने कहा कि आदित्यपुर निवासी प्रशिक्षु पायलट शुभ्रोदीप दत्ता का शव सुबह मिला, जबकि पटना निवासी पायलट कैप्टन जीत शत्रु आनंद का शव बाद में मिला। उन्होंने बताया कि विशाखापत्तनम से आई नौसेना की 19 सदस्यीय टीम लापता विमान की तलाश में लगातार जुटी है।

अधिकारियों के अनुसार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी), उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय (डीएफटी) और उड़ान योग्यता निदेशालय (डीएडब्ल्यू) के साथ घटना की जांच शुरू कर दी है।

'वीटी-टीएजे' के रूप में पंजीकृत विमान का स्वामित्व और संचालन करने वाली 'अल्केमिस्ट एविएशन' ने एक बयान में कहा कि दुर्घटना के कारणों के बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा।

इसने कहा, ''विमान में 80 लीटर ईंधन था और यह साढ़े चार घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम था तथा उड़ान का समय एक घंटा निर्धारित था।'' बयान में कहा गया कि मंगलवार पूर्वाह्न करीब 11.10 बजे विमान का संपर्क जमशेदपुर हवाई नियंत्रण कक्ष (एटीसी) से टूट गया।

बीआरएस ने कृषि ऋण माफी को लेकर किया राज्यव्यापी प्रदर्शन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

हैदराबाद/भाषा। तेलंगाना में विपक्षी भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने बृहस्पतिवार को पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया और कांग्रेस सरकार से कृषि ऋण माफी योजना को बिना शर्त लागू करने की मांग की। प्रदर्शन के तहत बीआरएस नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर रैलियां निकालीं, धरने दिए और नारे लगाए तथा सरकार से बिना किसी शर्त के सभी किसानों के दो लाख रुपए के ऋण माफ करने के अपने वादे को पूरा करने की मांग की।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव और पूर्व मंत्री टी हरीश राव सहित पार्टी नेताओं ने राज्य में विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शनों में भाग लिया। बीआरएस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों पर सभी किसानों को दो लाख रुपए तक की ऋण माफी के मामले में धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले दो मौकों पर फसल ऋण माफ करने का वादा किया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रही। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा, किसानों को बीआरएस द्वारा फैलाई गई अफवाहों में नहीं आना चाहिए। मेरी सरकार सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है। बीआरएस पर भरोसा मत कीजिए, जिसने दस साल तक तेलंगाना को लूटा है।

ओडिशा सरकार गंजाम जहरीली शराब कांड की आरडीसी से जांच कराएगी : मंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। ओडिशा सरकार जल्द ही गंजाम जिले में जहरीली शराब कांड की प्रशासनिक जांच मंडलीय राजस्व आयुक्त (आरडीसी) से कराने का आदेश देगी। राज्य के आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी अवैध देशी शराब की दुकानों को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

गंजाम जिले में सोमवार को कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 13 अन्य का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। हरिचंदन ने

आरडीसी जांच की घोषणा विधानसभा में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद कही। विपक्षी बीजू जनता दल (बीजद) ने यह मुद्दा उठाते हुए हरिचंदन के इस्तीफे की मांग की थी।

हरिचंदन ने कहा, ''मुख्यमंत्री जल्द ही गंजाम जिले में शराब से हुई मौतों की जांच मंडलीय राजस्व आयुक्त (आरडीसी) से कराने का आदेश जारी करेंगे।'' उन्होंने कहा कि आरडीसी दो महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंप देगे। हरिचंदन ने बताया कि राज्य सरकार ने अवैध शराब की गतिविधियों को सहन न करने की नीति अपनाई है और अधिकारियों को सख्त निगरानी रखने तथा राज्य भर में अवैध शराब निर्माण इकाइयों और दुकानों पर छापेमारी करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बेहरामपुर के आबकारी निरीक्षक रमेश चंद्र मोहंती और उप-निरीक्षक प्रसन्न कुमार ढाली को निलंबित कर दिया है।

आबकारी मंत्री ने बताया कि बेहरामपुर के आबकारी अधीक्षक प्रदीप पाणिग्रही का स्थानांतरण करने का आदेश दिया गया है। चिकिटी प्रखंड के माउंडपुर, जेनसाही और करबालुआ गांवों के करीब 20 लोग सोमवार शाम एक स्थानीय गैर-लाइसेंसी दुकान से देसी शराब पीने के बाद बीमार पड़ गए थे, जिनमें से दो की मौत हो गई।

ओडिशा 'सिमबॉक्स' गिरोह: ओडिशा पुलिस ने सीधे ढाका से 'सिमबॉक्स' के संचालन का किया दावा

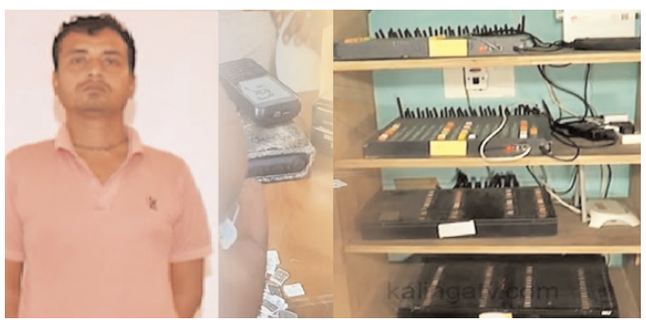

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

भुवनेश्वर/भाषा। भुवनेश्वर-कटक के पुलिस आयुक्त संजीव पांडा ने बृहस्पतिवार को एक बड़ा खुलासा किया कि यहां और रांची में स्थापित 'सिमबॉक्स' को सीधे बांग्लादेश के ढाका से नियंत्रित किया जाता था।

पांडा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि बांग्लादेश के फेनी में रहने वाले 30 वर्षीय असादुर रहमान ने पश्चिम बंगाल के राजू मंडल की मदद से 'सिमबॉक्स' संचालन शुरू किया था। उनके अनुसार मंडल रहमान के लिए स्थानीय मददगार है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि असादुर 'स्मार्ट स्विच' के मार्फत दूर से भुवनेश्वर एवं रांची में 'सिमबॉक्स' को नियंत्रित करता था जबकि कटक में 'सिमबॉक्स' का संचालन स्थानीय रूप से किया जाता था। पुलिस ने कहा कि उसे असादुर की तस्वीर समेत इस संबंध में विस्तृत सूचना मिली है। 'सिमबॉक्स' मूल फोन नंबर को छिपाने के लिए इस्तेमाल में लाये जाते हैं तथा इनका उपयोग साइबर अपराध, नफरत वाले भाषण, जबरन वसूली एवं अन्य अवैध गतिविधियों में किया जाता है। ऐसे में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए चुनौती पैदा हो जाती है।

पांडा ने कहा, ''वह ढाका में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता था एवं उसने पहले एक फैशन एवं प्रौद्योगिकी संस्थान से पढ़ाई की थी। जांच से खुलासा हुआ कि इस गिरोह में पाकिस्तान, चीन और पश्चिम एशिया से भारत में आने वाली अंतरराष्ट्रीय कॉल का मार्ग बदल दिया जाता था।'' हाल में ओडिशा से एक पुलिस दल झारखंड की राजधानी रांची गया था और उसने वहां मंडल द्वारा संचालित एक अन्य 'सिमबॉक्स' केंद्र पाया था। मंडल को 16 अगस्त को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया था। अबतक पुलिस ने कटक, भुवनेश्वर एवं रांची से 17 'सिमबॉक्स' जब्त किये हैं। पुलिस ने 678 चालू सिमकार्ड, तीन इंटरनेट कनेक्शन एवं अतिरिक्त सिमकार्ड भी जब्त किये हैं।

असम सरकार ने मुस्लिम निकाह-तलाक अधिनियम निरस्त करने के लिए विस में विधेयक पेश किया

गुवाहाटी/भाषा। असम सरकार ने बृहस्पतिवार को मुसलमानों के निकाह और तलाक के पंजीकरण संबंधी कानून को निरस्त करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। इसमें कहा गया कि मौजूदा अधिनियम में समुदाय के नाबालिगों के विवाह की अनुमति देने की गुंजाइश है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 और असम निरसन अध्यादेश 2024 को समाप्त करने के लिए असम निरसन विधेयक, 2024 विधानसभा में पेश किया। उन्होंने निरसन विधेयक पेश करने के उद्देश्य और कारण पर प्रकाश डालते हुए कहा, ''(पुरुष के मामले में) 21 वर्ष से कम आयु वाले और (महिला के मामले में) 18 वर्ष से कम आयु वाले इच्छुक व्यक्तियों के निकाह को पंजीकृत करने की गुंजाइश होती है।''

मोहन ने कहा कि पूर्व कानून में पूरे राज्य में अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कोई प्रावधान नहीं था और इसके कारण अदालत में भारी संख्या में मुकदमेबाजी हुई। उन्होंने कहा, ''अधिकृत लाइसेंसधारियों (मुस्लिम निकाह रजिस्ट्रार) के साथ-साथ नागरिकों द्वारा भी कम उम्र/नाबालिगों के बच्चे-बच्चियों के निकाह कराने और पक्षों की सहमति के बिना जबरन निकाह कराने के लिए इसका दुरुपयोग करने की गुंजाइश है।''

राहत सामग्री और आपदा प्रबंधन उपकरण लेकर एनडीआरएफ के दल त्रिपुरा पहुंचे : मुख्यमंत्री

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

अगरतला/भाषा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की कई टीम राहत सामग्री और आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव कार्यों में राज्य सरकार की सहायता करने के लिए पहुंच गयी हैं।

त्रिपुरा में रविवार से भूस्खलन और बाढ़ संबंधी घटनाओं में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई तथा एक व्यक्ति लापता हो गया है। भारी बारिश के कारण कम से कम 32,750 लोगों ने 330 राहत शिविरों में शरण ली है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा राज्य प्रशासन इस 'अभूतपूर्व' प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए 24 घंटे काम कर रहा है।

साहा ने सोशल मीडिया मंच 'फेसबुक' पर एक पोस्ट में कहा, एनडीआरफ की टीम राहत-सामग्री के साथ त्रिपुरा पहुंच गई है। अगरतला के महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य बहादुर हवाईअड्डे पर राहत सामग्री और आपदा प्रबंधन उपकरण को पहुंचा दिया गया है और अब इन्हें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत-बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए भेजा जाएगा। जरूरतमंद लोगों के लिए उम्मीद और सहायता लेकर आ रहे हैं।

साहा ने कहा, राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह जी से बात की। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ की कुल 11 टीम त्रिपुरा भेजी जाएंगी...बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए कई हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी। एनडीआरएफ टीम के साथ अधिक संख्या में नावें भी भेजी जाएंगी। मैं त्रिपुरा के लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा से फोन पर बात करके राज्य में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली और उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।

शाह ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के दलों के साथ-साथ नौकाएं और हेलीकॉप्टर भी राज्य में भेज रही है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डा. माणिक साहा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।

केंद्र राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय सरकार की सहायता के लिए राज्य में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम के अलावा नौका और हेलीकॉप्टर भी भेज रहा है।

पटना में पुलिस ने मादक पदार्थों के सिलसिले में व्यापक छापेमारी की, 176 लोग गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

पटना/भाषा। बिहार पुलिस ने पटना में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री जब्त करने के साथ इस सिलसिले में 176 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पटना पुलिस द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार बुधवार को चलाए गए इस अभियान को लेकर 54 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त और इसका उपभोग करने वाले 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बयान के मुताबिक जब्त की गयी प्रतिबंधित सामग्री में 10 ग्राम ब्राउन शुगर, 30 ग्राम स्मैक, 12.55 किलोग्राम गांजा (मारिजुआना) और कई अन्य सामान शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि पुलिस ने इसके अलावा 23 कार्टन विदेशी शराब और 896.50 लीटर देशी शराब भी जब्त की। पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार समेत पांच वाहन, एक पिस्तौल और एक कारतूस भी बरामद किया। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि गिरफ्तार किए गए लोगों का मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल अंतरराज्यीय गिरोहों से कोई संबंध तो नहीं है। अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिहार में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अवैध शराब की तस्करी लगातार एक गंभीर मुद्दा बनी हुई है जबकि तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

कांग्रेस जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने की इच्छुक : खरगे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

श्रीनगर/भाषा। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे ने जम्मू-कश्मीर के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अन्य विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने की बृहस्पतिवार को इच्छा जतायी और केंद्र शासित प्रदेश के लोगों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वादों को ''जुमला'' करार दिया।

खरगे ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के साथ बृहस्पतिवार को यहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनावों की जमीनी स्तर की तैयारियों के बारे में जानकारी ली। खरगे ने यहां संवाददाताओं से कहा, चुनाव की घोषणा के बाद यह पहली बैठक थी... हम यहां चुनाव और गठबंधन के लिए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय जानने के लिए आए हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की पहल की है। हम इस दिशा में काम करने का वादा करते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी की जम्मू कश्मीर में चुनाव पूर्व गठबंधन बनाने में रुचि है। खरगे ने कहा, राहुल गांधी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। 'इंडिया' गठबंधन ने एक तानाशाह को पूर्ण बहुमत के साथ (केंद्र में) सत्ता में आने से रोका। यह 'इंडिया' की सबसे बड़ी सफलता है।'' कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने कहा कि भाजपा

लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद चिंतित है, क्योंकि वे जिन विधेयकों को पारित कराना चाहते थे, उनमें से कुछ को या तो वापस ले लिया गया है या संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। खरगे ने दावा किया कि भाजपा अपने बहुमत का फायदा उठाकर कृषि कानून जैसे कानून पारित करती है। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा द्वारा किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। खरगे ने कहा, चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से किया गया एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। वे सभी (वादे) जुमले हैं। भाजपा ने पूर्ववर्ती राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया और यहां के लोगों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। खरगे ने कहा कि यहां कोई विधान परिषद, कोई पंचायत या नगर पालिका नहीं है। उन्होंने कहा, ''लोगों को लोकतंत्र से दूर रखा गया है।'' खरगे कहा उच्चतम न्यायालय के 30 सितंबर तक चुनाव कराने के निर्देश के कारण ही जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। खरगे ने कहा,''मैं भाजपा और (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी साहब से कहना चाहता हूं कि आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, आप लोगों की आवाज को दबाने में सफल नहीं होंगे। आप उनकी आकांक्षाओं को दबा नहीं सकते। लोकतंत्र में लोगों की आवाज ही मायने रखती है। हम लोगों की आवाज का समर्थन करना जारी रखेंगे।'' कांग्रेस प्रमुख ने कहा, ''हम लोगों के साथ रहेंगे। हम उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। यह हमारा वादा है।''

जम्मू-कश्मीर विस की सभी 90 सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दिया गया : फारुक अब्दुल्ला

श्रीनगर/भाषा। नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बृहस्पतिवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा की सभी 90 सीट पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा अब्दुल्ला के आवास पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की गई है। अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, ''हमारी बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में काफी अच्छी रही। गठबंधन सही रास्ते पर है और अल्लाह ने चाहा तो यह सुचारू रूप से चलेगा। गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस पर आज शाम हस्ताक्षर हो जाएंगे और गठबंधन सभी 90 सीट के लिए है।'' जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए तीन चरण के तहत चुनाव 18 सितंबर, 25 सितंबर और एक अक्टूबर को होंगे। नतीजे चार अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। अब्दुल्ला ने कहा, ''मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के (एमवाई) तारिगामी भी हमारे साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि हमे लोगों का साथ मिलेगा और हम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भारी बहुमत से जीतेंगे।'' इसके पहले दिन में गांधी ने आश्वासन दिया कि जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य के दर्जा को बहाल करना कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन की प्राथमिकता है।

सुविचार

यादें ही तो जिंदगी का खज़ाना हैं, बाकी तो सबको खाली हाथ ही जाना हैं!

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

खेलकूद में भविष्य

भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का यह कहना कि 'खेलों से भी अच्छी जिंदगी बन सकती है', कई लोगों की रूढ़िवादी सोच को बदलने की कोशिश है। मनु ने युवाओं को खेलकूद को करियर विकल्प के रूप में अपनाने की सलाह देकर उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है, जिसकी आज बहुत जरूरत है। भारत में स्कूली दिनों से ही विद्यार्थियों की सोच ऐसी बना दी जाती है कि उन्हें बड़े होकर सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करना है। उन्हें खेलकूद के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इस साल पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों और उनके पदकों की सूची देखें तो हम 71वें स्थान पर हैं! वहीं, उ. कोरिया, किर्गिस्तान, आर्मीनिया, चिली, द. अफ्रीका, अल्जीरिया जैसे देश भी हमसे ऊपर हैं। भारत 141 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके बावजूद हम पदकों की दौड़ में बहुत पीछे क्यों रह गए? एक राष्ट्र के तौर पर हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए। मनु भाकर ने खेलों को करियर विकल्प के तौर पर चुनने का आह्वान कर युवाओं को उम्मीद की एक किरण जरूर दिखाई है, लेकिन कड़वी हकीकत यह है कि पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। खेलकूद के लिए अच्छे और पर्याप्त मैदान नहीं हैं। कई जगह सार्वजनिक उद्यान जरूर हैं, वे भी अव्यवस्था और अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहे हैं। ऐसे में एक साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार का बच्चा यह कहे कि 'मैं खेलकूद के क्षेत्र में जाना चाहता हूं', तो सब लोग यही प्रतिक्रिया देंगे कि 'पढ़ ले भाई, इन बातों में कुछ नहीं रखा।'

परिवारों की आकांक्षाएं होती हैं और चिंताएं भी होती हैं। आकांक्षाएं ये कि बच्चा पढ़ जाएगा तो भविष्य में कुछ तो 'ठीक-ठाक' काम कर लेगा ... उसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी ... रिश्तेदारों के बीच रुतबा रहेगा ... पड़ोसी मान-सम्मान करेंगे। चिंताएं ये कि अगर खेलकूद में कुछ खास नहीं कर पाया तो भविष्य में क्या करेगा? सोशल मीडिया पर कई पूर्व खिलाड़ियों के दर्दनाक किस्से सुनने को मिलते हैं, जिन्हें गुजारा करने के लिए मेडल बेचकर मजदूरी करनी पड़ी। खिलाड़ी बनने में जोखिम कम नहीं है। मामूली-सी वजह पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया था। खेलकूद में चोट लगती रहती है, जिससे दिग्गज खिलाड़ी भी आशाजनक प्रदर्शन नहीं कर पाते। सरकारी व सामाजिक स्तर पर प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन पदक जीतने के बाद। ऐसे खिलाड़ियों के बारे में सबने पढ़ा होगा कि वे मुकाबले से पहले संसाधनों की किल्लत का सामना कर रहे थे। उस समय उनकी ओर सहयोग का हाथ बढ़ाने वाले कितने लोग होते हैं? जो खिलाड़ी आज पारिवारिक स्तर पर आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है, जिसके पास पहनने के लिए अच्छे जूते नहीं, पर्याप्त पोषण के लिए अच्छी गुणवत्ता का भोजन नहीं, बढ़िया साजो-सामान नहीं ... अगर उसे पहले ही सरकारी व सामाजिक स्तर पर पर्याप्त सहयोग मिल जाए तो प्रदर्शन यकीनन बेहतर होगा। एक और कड़वी बात यह है कि समाज में खेलों को गंभीरता से लिया ही नहीं जाता। उन्हें सिर्फ कुछ समय के मन-बहलाव का जरिया समझा जाता है। कई लोग यह कहते मिल जाते हैं कि 'खेलों में क्या रखा है, घर पर काम में हाथ बंटाओ, अपनेआप व्यायाम हो जाएगा!' वास्तव में वे खेलकूद की भावना से अपरिचित हैं। सिर्फ पसीना बहाने के लिए खेलकूद में भाग नहीं लिया जाता। इससे मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। खिलाड़ियों में एकता व सौहार्द की भावना मजबूत होती है। खिलाड़ी सहयोग व नेतृत्व कौशल जैसे गुण सीखता है। मनु भाकर के शब्दों में – 'मैं विफलता के बाद सफलता के स्वाद को जानती हूं। खेलों की यही खूबसूरती है। आप एक प्रतियोगिता में हारते हैं तो दूसरी में जीतते हैं, लेकिन ऐसा तभी होगा, जब आप लगातार कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे।' कोई खिलाड़ी मेडल न भी लाए, उसमें जूझने का जज्बा आ ही जाता है। अगर बच्चों को स्कूली दिनों से ही खेलकूद के लिए प्रेरित करेंगे तो वे भविष्य में कई शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे।

ट्वीटर टॉक

माताओं-बहनों की अटूट आस्था और अखंड सौभाग्य का प्रतीक पावन कजरी तीज के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की अनंत कृपा आपके जीवन में सदा बनी रहे, और आपको सुख, समृद्धि, और उत्तम स्वास्थ्य का प्रदान करें।

-दीया कुमारी

अखंड सौभाग्य और समृद्धि के प्रतीक पर्व कजरी तीज (भाद्रपद कृष्ण तृतीया) पर सभी देशवासियों, विशेषकर माताओं – बहनों को हार्दिक मंगलकामनाएं। मेरे संसदीय क्षेत्र के बूंदी जिले में आज के दिन लगने वाला मेला विशेष आकर्षण का केंद्र है।

-ओम बिरला

राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल बाबूलाल जी बैरवा की भांकरोटा पुलिस चौकी में आत्महत्या की ख़बर दु:खद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबूलाल जी ने मुख्यमंत्री के नाम सुसाइड नोट में आला अधिकारियों समेत कई लोगों पर उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगाया है।

-गोविंद सिंह डोटासरा

प्रेरक प्रसंग

सच्चाई की अभिव्यक्ति

फ्रेडरिक 1740 से 1786 तक प्रशिया के सम्राट रहे। वह एक कुशल शासक होने के साथ-साथ नाटक लिखने का भी शौक रखते थे। हर सप्ताह नाटक लिखते, अपने दरबारियों को सुनाते, और उनकी वाहवाही लूटते। इससे राजा को बड़ा नाटककार होने का भ्रम हो गया। उसी दौरान प्रशिया में प्रसिद्ध नाटककार वाल्टेयर की ख्याति चरम पर थी। फ्रेडरिक ने वाल्टेयर को अपना नाटक सुनाने के लिए दरबार में आमंत्रित किया। नाटक सुनने के बाद दरबारी वाहवाही करने लगे, पर वाल्टेयर ने साफ कहा कि दरबारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं और नाटक दोयम दर्जे का है। राजा यह सुनकर क्रोधित हुआ और वाल्टेयर को जेल में डाल दिया। कुछ साल बाद राजा ने फिर से वाल्टेयर को नाटक सुनाने के लिए बुलाया, यह सोचकर कि जेल की यातना के बाद वह उसके नाटक की प्रशंसा करेगा। राजा ने नाटक पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार वाल्टेयर सुनते-सुनते बीच में ही उठ खड़ा हुआ और जेल की ओर चल दिया। फ्रेडरिक ने पूछा, 'कहां जा रहे हो?' वाल्टेयर ने जवाब दिया, 'आपका यह नाटक सुनने से तो जेल की यातना अच्छी है।'

सामयिक

महिलाओं को समानता के पंख देने होंगे

ललित गर्ग

दुनिया भर में, महिलाओं को सशक्त बनाने, शिक्षा से लेकर राजनीति और आर्थिक भागीदारी तक विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने के प्रयासों को तीव्र गति देने के लिये महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। सन 1920 में इस दिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वां संशोधन स्वीकार किया गया था। यह दिन महिलाओं को पुरुषों के समान मानने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है, जिसने 1893 में महिला समानता की शुरुआत की। महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला वकील बेल्ला अब्जुग के प्रयास से 1971 से 26 अगस्त को 'महिला समानता दिवस' के रूप में मनाया जाने इस वर्ष की थीम है समता को अपनाएं, जो न केवल महिलाओं की व्यक्तिगत उन्नति के लिए बल्कि समाज की समग्र प्रगति के लिए भी महिलाओं को सशक्त बनाने के महत्व पर केन्द्रित है। यह व्यापक मानवाधिकारों और सतत विकास के साथ लैंगिक समानता के परस्पर संबंध पर जोर देता है।

महिला समानता दिवस से जुड़ा हुआ रंग बैंगनी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त, बैंगनी रंग महिलाओं और लैंगिक समानता का प्रतीक है। यह न्याय और गरिमा का प्रतिनिधित्व करता है, और अक्सर दूरदर्शी सोच और महिलाओं के अधिकारों के लिए चल रही लड़ाई को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। महिलाएं ही समस्त मानव प्रजाति की धुरी हैं। वो न केवल बच्चे को जन्म देती हैं बल्कि उनका भरण-पोषण और उन्हें संस्कार भी देती हैं। महिलाएं अपने जीवन में एक साथ कई भूमिकाएं जैसे- मां, पत्नी, बहन, शिक्षक, दोस्त बहुत ही खूबसूरती के साथ निभाती हैं। बावजूद क्या कारण है कि आज हमें महिला समानता दिवस मनाये जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये जरूरी है कि अधिक महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए भारत सरकार को जरूरी कदम उठाने होंगे। सरकार को अपनी लैंगिकवादी सोच को छोड़ना पड़ेगा।

भारत में महिलाओं की उपेक्षा, भेदभाव, अत्याचार एवं असमानता के कारण महिला समानता ज्यादा अपेक्षित है। भारत ने महिलाओं को आजादी के बाद से ही मतदान का अधिकार पुरुषों के बराबर दिया, परन्तु यदि वास्तविक समानता की बात करें तो भारत में आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी महिलाओं की स्थिति चिन्ताजनक एवं विसंगतिपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासन में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में काफी प्रगति देखी गयी है, खासकर शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे क्षेत्रों में। नारी शक्ति वन्दन अधिनियम-2023 के माध्यम से नारी शक्ति को राजनीति में समानता देने की शुरुआत हुई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी पहलों ने समाज में महिलाओं और लड़कियों की स्थिति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके अतिरिक्त, कार्यबल और नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ रही है। इन प्रगतियों के बावजूद, महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं। भारत में लैंगिक असमानता अभी भी व्याप्त है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहाँ महिलाओं को अक्सर शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक वेतन अंतर जैसे मुद्दे समानता की दिशा में प्रगति में बाधा डालते रहते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता हासिल करना भारत सहित विश्व भर में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बना हुआ है। समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने वाली नीतियों के माध्यम से इस असमानता को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत सरकार के खुद के कर्मचारियों में केवल 11 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिये अधिक एवं नये अवसर सामने आने जरूरी है। क्योंकि देश में ऐसी महिलाएं नजर आती हैं, जो सभी प्रकार के भेदभाव के बावजूद प्रत्येक क्षेत्र में एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं और सभी उन पर गर्व भी महसूस करते हैं। परन्तु इस कतार में उन सभी महिलाओं को भी शामिल करने की जरूरत है, जो हर दिन अपने घर में और समाज में महिला होने के कारण असमानता, अत्याचार एवं उपेक्षा को झेलने के लिए विवश है। आये दिन समाचार पत्रों में लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और बलात्कार जैसी खबरों को पढ़ा जा सकता है, परन्तु इन सभी के बीच वे महिलाएं जो अपने ही घर में सिर्फ इसीलिए प्रताड़ित हो रही हैं, क्योंकि वह एक औरत है। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) नाम के थिंक टैंक ने बताया है कि भारत में केवल 7 प्रतिशत शहरी महिलाएं ऐसी हैं, जिनके पास रोजगार है या वे उसकी तलाश कर रही हैं। सीएमआईई के मुताबिक, महिलाओं को रोजगार देने के मामले में हमारा देश इंडोनेशिया और सऊदी अरब से भी पीछे है। किसी देश या समाज में अचानक या सुनियोजित उथल-पुथल होती है, कोई आपदा, युद्ध एवं राजनीतिक या मनुष्यजनित समस्या खड़ी होती है तो उसका सबसे ज्यादा नकारात्मक असर स्त्रियों पर पड़ता है और उन्हें ही इसका खामियाजा उठाना पड़ता है।

दावोस में हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम ने अपनी एक रिपोर्ट 'टाइम टू केयर' में घरेलू औरतों की आर्थिक स्थितियों का खुलासा करते हुए दुनिया को चौंका दिया था। वे महिलाएं जो अपने घर को संभालती हैं, परिवार का ख्याल रखती हैं, वह सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक अनगिनत सबसे मुश्किल कामों को करती है। अगर हम यह कहें कि घर संभालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है तो शायद गलत नहीं होगा। दुनिया में सिर्फ यही एक ऐसा पेशा है, जिसमें 24 घंटे, सातों दिन आप काम पर रहते हैं, हर रोज क्राइसिस झेलते हैं, हर डेडलाइन को पूरा करते हैं और वह भी बिना छुट्टी के। सोचिए, इतने सारे कार्य-संपादन के बदले में वह कोई वेतन नहीं लेती। उसके परिश्रम को सामान्यतः घर का नियमित काम-काज कहकर विशेष महत्व नहीं दिया जाता। साथ ही उसके इस काम को राष्ट्र की उन्नति में योगभूत होने की संज्ञा भी नहीं मिलती। प्रश्न है कि घरेलू कामकाजी महिलाओं के श्रम का आर्थिक मूल्यांकन क्यों नहीं किया जाता? घरेलू महिलाओं के साथ यह दोगला व्यवहार क्यों? दरअसल, इस तरह के हालात की वजह सामाजिक एवं संकीर्ण सोच रही है। पितृसत्तात्मक समाज-व्यवस्था में आमतौर पर सत्ता के केंद्र पुरुष रहे और श्रम और संसाधनों के बंटवारे में स्त्रियों को हाशिये पर रखा गया है। सदियों पहले इस तरह की परंपरा विकसित हुई, लेकिन अफसोस इस बात पर है कि आज जब दुनिया अपने आधुनिक और सभ्य होने का दावा कर रही है। एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर कब तक सभी वंचनाओं, महामारियों एवं राष्ट्र-संकटों की गाज स्त्रियों पर गिरती रहेगी।

जहां देश में प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी और वर्तमान में राष्ट्रपति के पद पर द्रोपदी मुर्मू हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी राज्य की बागडोर संभाल रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष भी एक महिला मायावती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को तो विश्व की ताकतवर महिलाओं में शुमार किया ही जा चुका है। पूर्व में लोकसभा में विपक्ष की नेता के पद पर सुषमा स्वराज और लोकसभा अध्यक्ष के पद पर मीरा कुमार ने भी महिला के गौरव को बढ़ाया हैं। कॉरपोरेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर जैसे क्षेत्रों में इंदिरा नूई और चंदा कोचर जैसी महिलाओं ने अपना लोहा मनवाया है। वर्तमान में निर्मला सीतारमण सहित अनेक महिलाओं ने राजनीति में अपनी छाप छोड़ रही है। हमारी सेना में महिलाओं की यथोचित भागीदारी उसे ज्यादा शालीन, सामाजिक, योग्य और कारगर ही बनाएगी।

युगों से आत्मविस्मृत महिलाओं को अपनी अस्मिता और कर्तृत्वशक्ति का तो अहसास हुआ ही है, साथ ही उसकी व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व चेतना में क्रांति का ऐसा ज्वालामुखी फूटा है, जिससे भेदभाव, असमानता, रूढ़संस्कार जैसे उन्हें कमतर समझने की मानसिकता पर प्रहार हुआ है। पुरुषवर्ग महिलाओं को देह रूप में स्वीकार करता है, किन्तु आधुनिक महिलाओं ने अपनी विविधआयामी प्रतिभा एवं कौशल के बल पर उनके सामने मस्तिष्क एवं शक्ति बनकर अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है, वही अपने प्रति होने वाले भेदभाव का जबाव सरकार, समाज एवं पुरुषों को देने में सक्षम है, महिला समानता दिवस यदि उनकी सक्षमता को पंख दे रहा है तो यह जागरूक एवं समानतामूलक विश्व-समाज की संरचना का अभ्युदय है।

नजरिया

कानून का खौफ होता तो नहीं होता कोलकाता कांड

प्रियंका सौरभ

महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, अब हमारे पास ऐसे कानून हैं जो वस्तुतः अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध लगाते हैं और अदालतें उन जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार करती हैं जो अपने जीवन के लिए डरते हैं। स्वतंत्र भारत में आधुनिक समान नागरिक संहिता के लिए पहला नमूना लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण की बात करता है। हर स्तर पर महिलाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्र एजेंसी को छीना जा रहा है।

साल 2012 में दिल्ली के निर्भयाकांड के यौन हिंसा पर सख्त कानून बनाए गए और बलात्कार पर मौत की सजा का प्रावधान किया गया। इसके बावजूद यौन अपराध खत्म नहीं हुए । दुष्कर्म की प्रकृति अधिक आक्रामक, अधिक क्रूर हो गई है और एक हद तक सतर्कतावाद और गैंगस्टरवाद का एक रूप बन गई है। भारत में लगभग हर दिन क्रूर बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज होती है।हाल के वर्षों में भयावह यौन हमलों की रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। समाजशात्री कहते हैं कि यह नया भारत है जहां कानून का शासन पूरी तरह से टूट गया है, जिसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है, क्योंकि यह पितृसत्ता के बेधड़क अतिक्रमणों का दौर भी है। पीड़ितों के इर्द-गिर्द प्रचलित कलंक और पुलिस जांच में विश्वास की कमी के कारण बड़ी संख्या में बलात्कार की रिपोर्ट नहीं की जाती है। भारत की पंगु पड़ी आपराधिक न्याय प्रणाली में मामले सालों तक अटके रहने के कारण दोष सिद्धि दुर्लभ बनी हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में औसतन प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। वर्ष 2022 में पुलिस ने एक युवती के साथ कथित क्रूर सामूहिक बलात्कार और यातना के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इस युवती को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया गया था। 2022 में ही भारत में एक पुलिस अधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया था। उन पर एक 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है, जो अपने साथ हुए सामूहिक बलात्कार की रिपोर्ट करने के लिए उनके पुलिस स्टेशन गई थी। मार्च में, अपने पति के साथ मोटरसाइकिल यात्रा पर गई एक स्पेनिश पर्यटक के सामूहिक बलात्कार के बाद कई भारतीय पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। 2021 में मुंबई में एक 34 वर्षीय महिला की बलात्कार और क्रूरतापूर्वक प्रताड़ित किए जाने के बाद मृत्यु हो गई। निर्भयाकांड के बाद कोलकाता के आरजी कर रेप और हत्याकांड ने एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा अब तो आम हो गई है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर ट्रोल, जो हर मुखर महिला या उसकी बेटी को चुप कराना, गाली देना या बलात्कार करना चाहते हैं, उन्हें जवाबदेह नहीं बनाया जाता है। उल्लंघनकर्ताओं के पास बढ़ती हुई दंडमुक्ति और न्यायिक साधन भी राजनीतिक आकाओं के सामने आत्मसमर्पण करने के साथ, बलात्कार से लड़ना कठिन हो गया है। देश में महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों में वृद्धि, साथ ही देश की कठोर जाति व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर रहने वालों के साथ व्यवहार, ऊपर से नीचे तक दंडमुक्ति की संस्कृति के परिणामस्वरूप एक उत्साहजनक कारक के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के अधिक सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने और लगभग सभी क्षेत्रों में पुरुष आधिपत्य को चुनौती देने के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है। अधिकांश पुरुष अभिभूत हैं और नहीं जानते कि अपने आहत अहंकार को कैसे संभालें और व्यापक बेरोजगारी ने समग्र रूप से निराशा पैदा की है। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में मामलों के वर्षों तक अटके रहने के साथ दोषसिद्धि का निम्न स्तर भी ऐसे क्रूर अपराधों का जन्मदाता है। पुरुष अकसर यौन हिंसा का इस्तेमाल दमनकारी लिंग और जाति पदानुक्रम को मजबूत करने के लिए एक हथियार के रूप में करते हैं। बलात्कार की घटनाओं की संख्या में वृद्धि और मुखालफत के लिए अधिक संख्या में महिलाओं के आगे आने के बावजूद देश में सजा की दर कम बनी हुई है। कई मामलों में, सबूतों की कमी को अकसर कम सजा दर या उच्च न्यायालयों द्वारा सजा को पलटने का कारण बताया जाता है। कुछ साल पहले स्पेनिश पर्यटक के साथ जो हुआ वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और देश में अराजकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम जानते हैं कि यौन अपराधों की बहुत कम रिपोर्टिंग होती है और इसे बदलना होगा। अगर यह बलात्कार संस्कृति नहीं है, जिसे समाज के समझदार पुरुषों और महिलाओं, संस्थानों और सरकारी अंगों द्वारा समर्थित और बरकरार रखा जाता है, तो यह क्या है? आप सभी कानून, सभी तेज अदालतें, यहां तक कि मौत की सजा भी ला सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकता जब तक कि एक समान मानसिकता में बदलाव न हो जो लड़कियों और महिलाओं के बारे में सोचने का एक नया तरीका शुरू करे। हमने बलात्कार संस्कृति को खत्म करने का काम भी शुरू नहीं किया है। हमने पितृसत्ता को जलाने वाली माचिस भी नहीं जलाई है। दिसंबर 2012 में सरकार ने आखिरकार हमारी बात जरूर सुनी थी। एक पल के लिए ऐसा लगा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बजाय आज हम रुक गए हैं या इससे भी बदतर, पीछे चले गए हैं।

महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर, अब हमारे पास ऐसे कानून हैं जो वस्तुतः अंतरधार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध लगाते हैं और अदालतें उन जोड़ों को सुरक्षा देने से इनकार करती हैं जो अपने जीवन के लिए डरते हैं। स्वतंत्र भारत में आधुनिक समान नागरिक संहिता के लिए पहला नमूना लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण की बात करता है। हर स्तर पर महिलाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्र एजेंसी को छीना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि घर हमेशा एक सुरक्षित जगह है। डरावनी कहानियों में अनाचार और घरेलू हिंसा शामिल हैं। भारत में, जहां अंतरंग साथी द्वारा हिंसा की दूसरी सबसे बड़ी व्यापकता है, 46% महिलाएं कुछ परिस्थितियों में इसे स्वीकार्य मानती हैं – ससुराल वालों का अनादर करना या बिना अनुमति के घर से बाहर जाना। जब तक हम उन विचारों को नहीं बदल सकते, तब तक हम भारत की प्रतिष्ठा के नुकसान पर विलाप करते रहेंगे।

महत्त्वपूर्ण

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006. Editor : Bhupendra Kumar (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar. Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any suchmanner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.**Regn No.RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520**

पाठकों से अनुरोध है कि इस प्रकाशन में प्रकाशित किए जाने वाले किसी भी तरह के विज्ञापन (वैवाहिक, वर्गीकृत, टेंड़र एवं सजावटी इत्यादि) पर कोई भी कार्यवाही, प्रतिबद्धता या धनराशि का व्यय करने से पूर्व इन विज्ञापनों के बारे में समस्त जानकारी वह स्वयं प्राप्त कर लें। दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह उत्पादों की गुणवत्ता तथा सेवाओं के लिए विज्ञापनदाताओं द्वारा किए जा रहे किसी प्रकार के दावों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगर विज्ञापनदाता विज्ञापन में किया जा रहा दावा पूरा नहीं करता है तो दक्षिण भारत राष्ट्रमत समूह के संपादक, मुद्रक एवं प्रकाशक या मालिकान को पाठक किसी भी रूप में उत्तरदाई नहीं बना सकता।– **दक्षिण भारत राष्ट्रमत**

ईयू मिशन के तहत फ्रांसीसी पोत ने लाल सागर में क्षतिग्रस्त तेल टैंकर से 29 नाविकों को बचाया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

दुबई। लाल सागर में संदिग्ध हूती विद्रोहियों द्वारा किए गए सिलसिलेवार हमले में क्षतिग्रस्त तेल टैंकर पर सवार 29 नाविकों को यूरोपीय संघ मिशन के तहत एक फ्रांसीसी विध्वंसक पोत ने बचा लिया है। साथ ही इलाके में बम ले जाने वाली एक ड्रोन नौका को भी नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यमन के हूती विद्रोहियों पर यूनान के इस टैंकर 'सोयूनियन' पर हमला करने का संदेह है। यह हमला, पिछले कुछ हफ्तों में लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाकर किए गए हमलों में सबसे गंभीर हमला है।

यह हमला, गाजा पट्टी में इजराइल-हमास युद्ध के दौरान जहाजों को निशाना बनाने वाले हूती विद्रोहियों के महीनों लंबे अभियान के दौरान हुआ है। इन हमलों से यह अहम व्यापार मार्ग बाधित हुआ है। इस मार्ग से हर साल करीब 1000 अरब अमेरिकी डॉलर के माल की ढुलाई होती है।

यूरोपीय संघ के अभियान संचालकों ने बताया कि 'सोयूनियन' ने लाल सागर में लंगर डाल दिया है और अब अनियंत्रित होकर नहीं बह रहा है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि जहाज में अब भी आग लगी हुई है या नहीं। जहाज पर फिलीपीन और रूस के नाविक सवार थे।

सैन्य अधिकारियों ने बचाव कार्य में शामिल फ्रांसीसी विध्वंसक पोत का नाम नहीं बताया।

ब्रिटिश सेना से संबद्ध ब्रिटिश समुद्री व्यापार संचालन केंद्र (यूकेएमटीओ) ने बताया था कि छोटी-छोटी नौकाओं से आए हमलावरों ने बुधवार को यमन में विद्रोहियों के कब्जे वाले होदेइदिया बंदरगाह से करीब 140 किलोमीटर पश्चिम में जहाज को छोटे हथियारों से निशाना बनाया। उसने बताया कि जहाज पर चार रॉकेट भी दागे गए, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि ये मिसाइल से किए गए हमले हैं या ड्रोन से दागे गए रॉकेट।

हूती विद्रोहियों ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन पूर्व में भी वे ऐसे हमलों की जिम्मेदारी घटना के कई घंटे या कई दिन बाद लेते रहे हैं।

पिछले साल अक्टूबर में गाजा पट्टी में इजराइल-हमास युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक हूती विद्रोहियों ने करीब 80 जहाजों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। उन्होंने एक जहाज पर कब्जा कर लिया, जबकि दो को डुबो दिया और इस दौरान चार नाविक मारे गए।

प्रदर्शन

हैदराबाद में गुरुवार को के. टी. रामा राव ने पूर्व मंत्री सबिता रेड्डी, एमएलसी मोहम्मद महमूद अली और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किसानों को 2 लाख रुपये की ऋण माफी के अपने वादे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

संयुक्त राष्ट्र की टीम प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जांच के लिए बांग्लादेश पहुंचेगी

ढाका/भाषा। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना के इस्तीफे से पहले और उसके बाद कम से कम 650 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की जांच के लिए बृहस्पतिवार को बांग्लादेश पहुंचेगी।

अखबार 'डेली स्टार' ने ढाका में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी के हवाले से बुधवार को कहा, ''संयुक्त राष्ट्र की तथ्यान्वेषण टीम के आने और (अत्याचारों की) जांच करने से पहले यह संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की प्राथमिक टीम है। हम जांच के लिए रूपरेखा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद कर रहे हैं।'' अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र की टीम एक जुलाई से 15 अगस्त के बीच हुईं मानवाधिकार उल्लंघन की सभी घटनाओं की जांच के लिए विस्तृत नियम और शर्तों पर चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल कम से कम एक सप्ताह तक यहां रहेगा और नागरिक समाज समूहों, मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों तथा अन्य संबंधित लोगों से मुलाकात करेगा।

हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अराजकता फैल गई और हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच वह पांच अगस्त को भारत भाग गईं। इससे पहले, सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जुलाई के मध्य से 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई।

नोकिया चंद्रमा पर मानव मिशन के लिए एक्सिओम के स्पेससूट को मोबाइल नेटवर्क से लैस करेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। नोकिया ने उच्च गति वाली 4जी/एलटीई संचार क्षमताओं से अगली पीढ़ी के स्पेससूट को जोड़ने के लिए एक्सिओम स्पेस के साथ करार किया है। इन स्पेससूट का इस्तेमाल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव को उतारने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महत्वाकांक्षी योजना आर्टेमिस-3 मिशन में किया जाएगा।

आर्टेमिस-3 मिशन 2026 में प्रक्षेपित किये जाने की संभावना है और नोकिया की योजना चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क बनाने की है, जो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष सूट में अंतर्निहित होगा।

कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि नोकिया और एक्सिओम स्पेस, एक्सिओम एक्स्ट्राव्हीकुलर मोबिलिटी यूनिट (एएक्सईएमयू) में उच्च गति वाले सेलुलर नेटवर्क क्षमताओं को शामिल करेंगे, जो चंद्रमा पर कई किलोमीटर तक एचडी वीडियो, टेलीमेट्री डेटा और ध्वनि प्रसारण में मदद करेगा।

एक्सिओम स्पेस की एक्स्ट्राव्हीकुलर गतिविधि के कार्यकारी उपाध्यक्ष रसेल राल्स्टन ने एक बयान में कहा, ''चंद्रमा पर उच्च गति वाला 4जी/एलटीई नेटवर्क अंतरिक्ष यात्रियों का पृथ्वी से संचार स्थापित कराने में एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करेगा, जिससे महत्वपूर्ण डेटा का आदान-प्रदान सुगम होगा, तथा लंबी दूरी पर एचडी वीडियो संचार संभव होगा।''

इस प्रगति से आर्टेमिस-3 चालक दल के सदस्य 'रियल टाइम' वीडियो बना सकेंगे और चंद्र सतह का पता लगाने के दौरान पृथ्वी पर मिशन नियंत्रकों के साथ संवाद कर सकेंगे।

इसरो की गगनयान परियोजना के लिए प्रशिक्षित एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री, नासा एक्सिओम स्पेस-एएक्स-4 के हिस्से के रूप में अगले साल अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरने वाला है।

नोकिया ने इंट्यूटिव मशीन के आईएम-2 मिशन के हिस्से के रूप में चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसे इस साल के अंत में प्रक्षेपण स्थल पर पहुंचाया जाना है।

उस मिशन के दौरान, नोकिया का लक्ष्य यह प्रदर्शित करना है कि सेलुलर कनेक्टिविटी भविष्य के चंद्र या मंगल मिशन के दौरान महत्वपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान कर सके।

नोकिया में बेल लैब्स सॉल्यूशन्स रिसर्च के अध्यक्ष थिएरी ई. क्लेन ने कहा, ''हम उन्हीं मानक-आधारित प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं जो प्रतिदिन पृथ्वी पर अरबों उपकरणों को जोड़ती हैं। साथ ही अंतरिक्ष में पेश आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिए नये नवाचार और प्रौद्योगिकियां ला रहे हैं।''

टेक्सास में 90 फुट ऊंची हनुमान की मूर्ति बनी वहां की नई पहचान

ह्यूस्टन/भाषा। ह्यूस्टन के निकट भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया गया है जो अमेरिका के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य में एक नया अध्याय'' है।

यह मूर्ति टेक्सास में नवीनतम पहचान बन गई है जो बहुत दूर से दिखाई देती और यह अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है।

आयोजकों ने बताया कि इस मूर्ति का नाम 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' रखा गया है और यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। इसकी कई अन्य विशिष्टताएं भी हैं: यह भारत के बाहर हनुमान की सबसे ऊंची मूर्ति है, टेक्सास में सबसे ऊंची मूर्ति है, अमेरिका में तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है और इससे ऊंची मूर्तियां केवल न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (151 फुट)

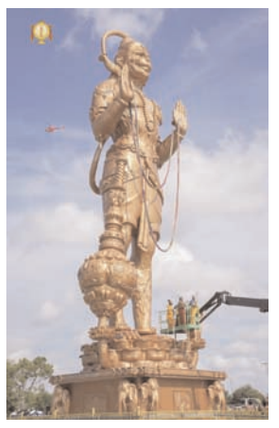

और फ्लोरिडा के हैलैंडेल बीच में पेगासस एंड ड्रैगन (110 फुट) ही हैं।

आयोजकों ने बताया कि 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' हनुमान मूर्ति का अनावरण यहां से करीब 35 किलोमीटर दूर शुगर लैंड स्थित श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में 15 से 18 अगस्त तक आयोजित भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह के दौरान किया गया। उनके अनुसार, यह मूर्ति 'निस्वार्थता, भक्ति और एकता' का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का यह नाम -'स्टैच्यू ऑफ यूनियन'- 'भगवान राम और सीता के पुनर्मिलन में हनुमान की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में' रखा गया है।

एक बयान में आयोजकों ने कहा, यह विस्मयकारी संरचना पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध वैदिक विद्वान परम पावन श्री चिन्ना जीयर स्वामीजी के दूरदर्शी प्रयासों का परिणाम है, जिन्होंने इस परियोजना को उत्तरी अमेरिका के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा था।

मुलाकात

भुवनेश्वर में गुरुवार को ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में भारतीय हॉकी टीम से मुलाकात करते हुए।

अदिति शर्मा ने 'खतरों के खिलाड़ी 14' के सफर पर कहा

'हर स्टंट से पहले डर लगता था'

मुंबई/एजेन्सी

अभिनेत्री अदिति शर्मा को 'खतरों के खिलाड़ी 14' (केकेके 14) से बुधवार को निकाल दिया गया। स्टंट आधारित रियलिटी शो के बारे में उन्होंने बताया कि इस शो में 'डर का सामना करना रोमांचक था।' इंस्टाग्राम पर अदिति ने कई तस्वीरें शेयर कीं। तस्वीरों में 'रब से है दुआ' की अभिनेत्री अपनी चोटों के निशान दिखा रही हैं, जो उन्हें स्टंट के दौरान लगी थीं। उन्होंने अपनी टीम, क्रू और अन्य प्रतियोगियों निमृत कौर अहलूवालिया और करण वीर मेहरा के साथ तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों के साथ, अदिति ने अपने 'केकेके 14' के सफर को समेटते हुए एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा। नोट में उन्होंने लिखा, मैं कुछ समय से चुप थी, अपने 'केकेके 14' के सफर को खत्म करने के साथ आई भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। मैं आखिरकार साझा करने के लिए तैयार हूं... हालांकि वह अध्याय बंद हो गया है, लेकिन मैंने जो यादें बनाई हैं, वे जीवन भर रहेंगी। मैं हर स्टंट से पहले डरी हुई थी, लेकिन उन डर का सामना करना रोमांचक था! उन्होंने कहा, यह यात्रा भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन मेरी निजी यात्रा अभी शुरू हुई है। मैं इस अनुभव को अविस्मरणीय बनाने वाले अविश्वसनीय क्रू और कलाकारों को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं - आपका समर्थन और सौहार्द मेरे लिए सब कुछ है। और मेरे अद्भुत दोस्तों, परिवार और फैन्स को, प्यार और प्रोत्साहन का निरंतर स्रोत होने के लिए धन्यवाद - यही मेरे लिए सब कुछ है। अभिनेत्री चेतना पांडे ने अदिति के पोस्ट पर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, मुझे पता है कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रही हैं... मैं भी उसी रास्ते से गुज़री हूं... लेकिन मेरा विश्वास करो, आप खुद को जितना मजबूत समझती हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं... और इस अविश्वसनीय और चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद आप अपने आप को अपने व्यक्तित्व के शिखर पर पाएंगी... लव यू। करण वीर ने टिप्पणी की, आप अद्भुत लड़की हैं... आपको और शक्ति मिले। उन्होंने यह भी लिखा: बिच्छू रानी। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ भी 'केकेके 14' का हिस्सा थीं। उन्होंने कमेंट सेक्शन में लाल दिल वाले इमोजी शेयर किए।

'रेस 4' में काम करेंगे सैफ अली खान!

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान फिल्म रेस 4 में काम करते नजर आ सकते हैं। रमेश तौरानी निर्मित रेस फ्रेंचाइजी के तीन पार्ट रिलीज हो चुके हैं। इनमें से रेस और रेस 2 में सैफ अली खान लीड रोल में नजर आए थे, वहीं रेस 3 में सलमान खान नजर आए थे।सैफ अली खान को रेस 4 में फिर से कास्ट किया जा सकता है। रेस फ्रेंचाइजी की शुरुआत वर्ष 2008 में प्रदर्शित फिल्म रेस से हुई थी। इस फिल्म में सैफ अली खान के साथ अक्षय खन्ना और अनिल कपूर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इसके बाद साल वर्ष 2013 में प्रदर्शित रेस 2 में सैफ अली खान और अनिल कपूर के साथ जॉन अब्राहम नजर आयें। वर्ष 2018 में रेस 3 में सलमान खान के साथ बॉबी देओल नजर आये। अब रेस 4 बनने की चर्चा जोरों पर है और इसमें सैफ मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। रेस 4 को लेकर निर्माता रमेश तौरानी की सैफ अली खान के साथ लंबे समय से बातचीत चल रही थी। कहा जा रहा है कि अब दोनों के बीच सहमति बन गई है। रमेश तौरानी अगले साल की पहली तिमाही में इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं।

हेमा समिति की रिपोर्ट के बीच तनुश्री दत्ता ने पूछा - मुझे न्याय कब मिलेगा

मुंबई/भाषा

न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद अभिनेत्री तनुश्री दत्ता ने कहा कि जब तक सत्ता में बैठे लोग अपराधियों को बचाते रहेंगे, कोई भी आंदोलन या रिपोर्ट बदलाव नहीं ला पाएगी। रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न और यौन शोषण को उजागर किया है। दत्ता ने 2018 में अभिनेता नाना पाटेकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसे भारत की 'मी टू मुहिम' कहा गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी न्याय का इंतजार है। हालांकि, पाटेकर ने आरोपों से इनकार किया है। अभिनेत्री ने न्यायमूर्ति हेमा समिति की विस्तृत रिपोर्ट के समर्थन में आगे आईं महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त की। रिपोर्ट मंगलवार को सार्वजनिक की गई। अभिनेता दिलीप से जुड़े 2017 के अभिनेत्री हमला मामले के बाद मलयालम सिनेमा में यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया था।

दत्ता ने 'पीटीआई-भाषा' को दिये एक साक्षात्कार में कहा, ''ऐसा लगता है कि मी टू आरोपियों की थीम यही है, जैसे वे समाज के सामने एक सभ्य छवि पेश करते हैं और (जब) उनकी छवि टूटती है, तो उनका अहंकार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं केरल की पीड़िताओं के लिए बहुत दुखी हूं। इन रिपोर्टों से कुछ नहीं होगा क्योंकि महिलाओं पर अब भी हमले और शोषण जारी है।'

' उन्होंने कहा, ''इस देश में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं - चाहे आप मिस इंडिया हों, अभिनेत्री हों, शिक्षित हों या सफल व्यक्ति हों। जब तक सत्ता में बैठे लोग इन अपराधियों को बचाने की कोशिश करेंगे, कोई भी आंदोलन, कोई भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकता।'' उन्होंने कहा, ''एक समिति की रिपोर्ट है, विशाखा समिति है, और ऐसी अनेक रिपोर्टें हैं तथा समितियां बनाई जा रही हैं, लेकिन आप व्यवस्था का पालन कैसे करेंगे, जब कानून व्यवस्था इतनी भ्रष्ट हो और अवैध रूप से अर्जित धन का इस्तेमाल इसे रिश्वत देने के लिए किया जाता हो?'' विशाखा दिशानिर्देश, जो 1997 में उच्चतम न्यायालय द्वारा तैयार किए गए थे, निजी या सार्वजनिक, संगठनों के लिए, यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण के लिए एक समिति गठित करना अनिवार्य करते हैं। दत्ता ने 2018 में आरोप लगाया था कि पाटेकर ने 2009 की फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के सेट पर डांस स्टेप दिखाने के बहाने उन्हें अनुचित तरीके से छुआ था। उन्होंने पाटेकर, नृत्य निर्देशक गणेश आचार्य, निर्देशक राकेश सारंग और फिल्म के निर्माता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। दत्ता के अनुसार, उन्होंने 14 गवाहों के नाम बताए थे, लेकिन पुलिस ने उनमें से किसी का भी बयान नहीं दर्ज किया और 'बी समरी' रिपोर्ट संलग्न करने का प्रयास किया, जिसका अर्थ है कि पुलिस के पास किसी आरोपी पर आरोप दर्ज करने या मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा, ''मेरे गवाहों ने मुझे बताया कि उन्हें पीसीओ से धमकी भरे फोन आए और पुलिस ने कभी उनसे किसी बयान के लिए संपर्क नहीं किया। एक पुरुष गवाह अपने गांव भाग गया, एक व्यक्ति पश्चिम एशिया चला गया और एक महिला गवाह डर के कारण कभी सामने नहीं आई।'' उन्होंने कहा, ''पांच साल बाद, हमारी एक विरोध याचिका पर अदालत की तारीख आई है, जो अगले महीने है। पांच साल सिर्फ केस को खुला रखने के लिए! मुझे न्याय कब मिलेगा?'' उन्होंने कहा, ''मैं भी किसी की बेटी हूं, क्या मुझे इस देश में रहने और सुरक्षित महसूस करने का अधिकार नहीं है?'' दत्ता ने दावा किया, ''2022 में, मैं उज्रैन में एक दुर्घटना का शिकार हुई, जब किसी ने उस ऑटो के ब्रेक काट दिए जिसमें मैं यात्रा कर रही थी। यह संयोग नहीं था क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, बल्कि दो बार हुआ।''

जैकलीन फर्नांडीज ने की रुद्राभिषेक पूजा

मुंबई/एजेन्सी

सावन में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने अपने आवास पर भगवान शिव के लिए 'रुद्राभिषेक पूजा' की, और उनके साथ मॉडल अनुषा दांडेकर भी थीं। इंस्टाग्राम स्टोरी पर जैकलीन के 70.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपनी स्टाइलिस्ट नमिता अलेक्जेंडर द्वारा पोस्ट किया गया एक वीडियो फिर से साझा किया, जिसमें एक पुजारी को रुद्राभिषेक करते हुए देखा जा सकता है, जो एक वैदिक अनुष्ठान है जिसमें भगवान शिव की उनके 'रुद्र' रूप में पूजा की जाती है और पवित्र स्नान कराया गया।

कैप्शन में नमिता ने लिखा, ''सबसे दिव्य रुद्र पूजा।'' जैकलीन ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें हम उन्हें पेस्टल गुलाबी रंग की पोशाक पहने और अपने प्यारे दोस्त - अपनी बिल्ली को बाहों में पकड़े हुए देख सकते हैं। अनुषा इंडिगो रंग का आकर्षक सूट पहने हुए उनके बगल में बैठी हैं। वे पूजा समारोह का जमकर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। जैकलीन ने इसे कैप्शन दिया: सभी के लिए शांति और आशीर्वाद। श्रीलंकाई अभिनेत्री और मॉडल जैकलीन ने 2009 में सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित फंतासी एक्शन कॉमेडी 'अलादीन' से अभिनय की शुरुआत की। फिल्म में अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और रितेश देशमुख ने अभिनय किया था।

इसके बाद उन्होंने 2010 के कॉमेडी ड्रामा 'हाउसफुल' में एक विशेष नंबर 'आपका क्या होगा' में अभिनय किया। एक्ट्रेस 'रेस 2', 'किक', 'रॉय', 'ब्रदर्स', 'हाउसफुल 3', 'ढिशूम', 'ए जेंटलमैन', 'जुड़वा 2', 'रेस 3', 'ड्राइव' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उन्हें आखिरी बार राज मेहता द्वारा निर्देशित और स्टार स्टूडियो धर्मा प्रोडक्शंस, मैजिक फ्रेम्स, पृथ्वीराज प्रोडक्शंस और केप ऑफ गुड फिल्म्स द्वारा निर्मित 2023 कॉमेडी-ड्रामा 'सेल्फी' में 'दीवाने' गाने में एक विशेष भूमिका में देखा गया था। फिल्म में अक्षय कुमार और इमरान हाशमी हैं। जैकलीन की अगली फिल्म 'फतेह' और 'वेलकम टू द जंगल' पाइपलाइन में है। अनुषा आखिरी बार फिल्म 'जूना फर्नीचर' में नजर आई थीं। वह 'एमटीवी रॉक ऑन', 'इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल', 'एमटीवी लव स्कूल' और 'सुपरमॉडल ऑफ द ईयर' जैसे रियलिटी शो की होस्ट रही हैं।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

www.dakshinbharat.com
epaper.dakshinbharat.com

चेन्नई | शुक्रवार | 23-08-2024 /dakshinbharat /dakshinbharat DAKSHIN BHARAT RASHTRAMAT HINDI DAILY

RNI No. : TNHIN/2013/52520
Regn No. : TN/CCN/613/2014-2016
posted at Patrika Channel,
Egmore RMS, Chennai-8

थोड़ी-सी भिन्नता के कारण व्यक्ति के मन में विचार बदलते हैं। अलग-अलग ज्ञान, दर्शन देखते हैं तो मन ऊपर-नीचे हो जाता है। व्यक्ति सत्य से विमुख हो जाता है। सत्य यानी जो शाश्वत, स्थायी हो, हमेशा आपके साथ चलता रहे। ऐसे सत्य का दर्शन कराने वाले, उसे जोड़कर रखने वाले परमात्मा का दर्शन है। वहां भी हमारा मिथ्यात्व शुरू हो जाता है। मिथ्यात्व मोहनीय कर्म का उपशम भी होता है। उपशम यानी हमारे कर्मों को दबा देना। जैसे पानी में फिटकरी डालने से उसमें रही हुई गंदगी नीचे जमा हो जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है।

संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए धर्म जरूरी है : युवाचार्य महेंद्रऋषि

एएमकेएम जैन मेमोरियल सेंटर मे धर्मसभा मे उमड़ रहा है श्रध्दांलुओ का सैलाब

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। गुरुवार को एएमकेएम जैन मेमोरियल सेंटर के आनंद दरबार मे श्रमण संघीय युवाचार्य महेंद्रऋषिजी ने उपस्थित जनों को धर्म उपदेश प्रदान करते हुए कहा कि जैन दर्शन उपदेश नहीं किंतु आदर्श पर कार्य करने वाला है। तीर्थंकरों ने अपनी नीगोद से प्रारंभ हुई यात्रा को सिद्धत्व तक पहुंचाया। उनका आदर्श हमारे समक्ष है। गर्भस्थ जीव ऐसा कुछ करता है कि वह देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होता है। वह जो कर सकता है, वह हम भी पा सकते हैं। उसके पास तो कम अवसर है। वह दूसरों पर निर्भर रहता है।

उन्होंने कहा कि हमारे पास अवसर है। हम प्रवचन श्रवण, स्वाध्याय कर सकते हैं। जिसकी तीनों कषायें उपशांत है, वह आत्मा श्रमण, ब्राह्मण के मुख से धार्मिक सुवचन श्रवण करे तो उसका कल्याण निश्चित है। उन्होंने कहा कर्मबंध में आने से दुःख का कारण बनता है। हर आत्मा कर्मों से मुक्त होना चाहती है। जिसके लिए बंधनों को तोड़ दिया या वह प्राप्त कर लिया, वह बंधन से मुक्त होने की श्रद्धा उसके पास है। उसके पास समझ है। उसकी समझ का उपयोग मां के माध्यम से प्रवचन श्रवण, धर्म आराधना सुनी, धर्म के वचन सुनने का अवसर मिला। अगर कोई भी माता अपने शिशु को संस्कारित करना चाहती है, वह स्वस्थ रहे। शिशु सुसंस्कृत हो, उसके लिए धर्म श्रवण जरूरी है। धर्ममय जीवन चर्या होनी आवश्यक है। जिन संस्कारों में वह शिशु को ढालना चाहती है, वैसा ही वातावरण आसपास में होना चाहिए। विकृतियों को आमंत्रित किया तो उसका असर मां के ऊपर भी पड़ेगा और शिशु पर भी पड़ेगा।

महासती अणिमाश्री जी ने कहा कि तीन लोक में सार धर्म ही है। धर्म ही भव सागर से उबारने वाला है। हम तो भाग्यशाली हैं कि आगमों के माध्यम से हमें जिनेश्वर भगवान के वचन मिले हुए हैं। जहां जिनवाणी श्रवण का अवसर मिले, उसे गंवाना नहीं है। घटते हुए पुण्यों के बीच हमें धर्म आराधना में लीन होना है। जिनवाणी हमारी आत्मा को निर्मल बनाने वाली है। धर्म आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। धर्मसभा में सुश्राविका श्वेता जांगड़ा ने 25 उपवास,सीमा संजय तातेड़ ने 21 उपवास आदित्य प्रवीण कवाड़ ने 9 उपवास के प्रत्याख्यान लिए। महासंघ के महामंत्री धर्मीचंद सिघंवी ने बताया कि मेवाड़ संघ मुम्बई के पदाधिकारियों व सदस्यों ने युवाचार्य महेन्द्रऋषिजी के दर्शन कर वर्ष 2025 चातुर्मास के लिए निवेदन किया।

डीजीवीसी का छात्रावास संस्थापक दिवस समारोह सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय द्वारकादास गोवर्धनदास वैष्णव कॉलेज के आधुनिकतम सुविधा सम्पन्न सेठ पुरुषोत्तमदास गोकुलदास छात्रावास का संस्थापक दिवस समारोह कालेज परिसर में धूमधाम से मनाया गया। ज्ञातव्य है कि इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1964-65 में कुलपति लक्ष्मणस्वामी मुदलियार ने हाथों हुई थी। पद्मभूषण बाबूभाई एम ने सत्रारंभ किया। इस छात्रावास में 292 छात्रों के लिए आवासीय व्यवस्था है । 4 डबल बेड के वातानुकूलित गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया है ।

महाविद्यालय के पूर्व सचिव एवं सेठ पुरुषोत्तमदास के परिवार के सदस्य पी हरिदासने इस समारोह का उदघाटन किया और सेठ श्री पुरुषोत्तमदास गोकुलदास की याद में इसी नाम से छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए पुस्तकालय की स्थापना की ।

इस अवसर पर हरिदास परिवार का सम्मान किया गया। छात्रावास के उप प्रबन्धक डॉ उमापति ने समारोह का संचालन किया व धन्यवाद दिया।

'ताम्बरम की अपनी पहचान' सहायक साहित्य का हुआ विमोचन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। अपर मंडल रेल प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी तेजप्रताप सिंह के निदेशानुसार हिंदी विभाग ने गुरुवार को 'ताम्बरम की अपनी पहचान' नामक सहायक साहित्य का विमोचन वरिष्ठ मंडल बिजली इंजीनियर, चल स्टाक, ताम्बरम शिवकृष्ण महेशहुनि ने किया। मंडल बिजली इंजीनियर, चल स्टॉक, वेलचेरी ए.रामचन्द्रन ने प्रथम प्रति प्राप्त की। इसमें ताम्बरम में होने वाले सभी रेलवे गतिविधियों का विवरण हैं, साथ ही ताम्बरम एवं उसके आसपास देखने लायक स्थानों का भी विवरण दिया गया है। शीघ्र ही इसे जनता के लिए वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी ए.श्रीनिवासन ने हिंदी माह की आवश्यकताओं को बताते हुए कार्यशाला कर संचालन किया। वरिष्ठ अनुवादक अशोक राम व मुख्य कार्यालय अधीक्षक पीजे जॉय ने कार्यक्रम का समन्वय किया।

भाव बिगड़ा तो भव बिगड़ा: साध्वीश्री राजमती

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। शहर के साहूकारपेट स्थित जैन भवन में चातुर्मासार्थ विराजित साध्वी राजमतीजी ने कहा कि वीतराग प्रभु महावीर की वाणी में पूर्णः श्रद्धा और आस्था को रखने वाले को जरूर मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके लिए मन में भाव अच्छे रखने चाहिए भाव बिगड़ा तो मनुष्य की अगली गति भी बिगड़ जाती हैं। □

उन्होंने कहा कि मनुष्यों की शारीरिक संरचना भले ही एक तरह की होती है लेकिन उनका आचरण अलग अलग होता है। साध्वी ने गौस्वामी तुलसीदास को उद्धरित करते हुए कहा कि दान देने से यदि धन की कमी होती है तो उसकी चिंता नही करनी चाहिए। इससे पूर्व साध्वी विनयश्रीजी ने कहा कि मनुष्य को आसक्ति और लोभ से बचना चाहिए, क्योंकि आसक्ति से ही वियोग उत्पन होता है और वियोग से मानव को दुख होता है। विदुषी साध्वी ने कहा कि अपने परिवार में सन्तान या धन की प्राप्ति होती है तो आसक्ति और मोह होता है और जब वो चली जाती है तब मन में विषाद उत्पन हो जाता है।

मानवता को सभ्यता सिखाने वाले प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के जीवन प्रसंग पर व्याख्यान माला में साध्वीश्री ने कहा कि तीर्थंकर ऋषभदेव के पहले लिपी, ज्ञान, विज्ञान, संयम, आहार, विहार और सेवा आदि के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। भगवान ऋषभदेव ने लोगों को इन चीजों के बारे में प्रबोधित किया था। प्रत्येक व्यक्ति को संयम लेने की भावना रखनी चाहिए और बिना प्रमाद रखे शुभ कार्य को कर लेना चाहिए।

साध्वी विनय श्री जी ने अपने संयम का श्रेय अपनी दादी मां को देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सन्तानों को विरक्त होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। संघ के अध्यक्ष प्रकाशचन्द खिवसरा ने सभी का स्वागत किया। महासचिव संजय पिंचा ने संचालन किया।

'दि साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर-एंपावरिंग मिलियंस ऑफ विमेन' का हुआ विमोचन

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक एवं एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉ सौम्या स्वामीनाथन ने चेन्नई में डॉक्टर कल्पना शंकर की आत्मकथा दि साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एंपावरिंग मिलियंस ऑफ़ वीमेन का विमोचन किया। डॉक्टर कल्पना शंकर की यह पुस्तक उनके परमाणु वैज्ञानिक से उद्यमिता में आगे बढ़ने की असाधारण यात्रा का वर्णन करती है। आत्मकथा विमोचन के इस कार्यक्रम में जोहो कारपोरेशन के संस्थापक श्रीधर वेंबू, सीरियल उद्यमी स्वाती मार्टिन लेखक एवं उद्यमी अबू हसन सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कोयंबतूर व तिरुपुर तेरापंथ महिला मंडल ने आयोजित किया चित्त समाधि शिविर

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

कोयम्बतूर। यहां गांधी पार्क स्थित तेरापंथ भवन में अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के निर्देशानुसार स्थानीय कोयंबतूर व तिरुपुर तेरापंथ महिला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में मुनिश्री दीपकुमारजी के सान्निध्य में चित्त समाधि शिविर का आयोजन किया गया। अध्यक्ष मंजू सेठिया ने सभी का स्वागत किया। तिरुपुर महिला मंडल की सदस्याओं ने प्रेरणा गीत का संगान किया।

मुनिश्री काव्यकुमारजी ने कहा कि अपने जीवन में नकारात्मक की बातों से बचें व बीती हुई बातों को भूलने का प्रयास करें। चित्त में समाधि लाना है तो प्रसन्न रहने का व वर्तमान में जीने का प्रयोग करें। मुनिश्री दीपकुमारजी ने मंगल भावना का सामूहिक उच्चारण करवाया तथा प्रतिदिन चित्त में समाधि का विकास करने का तरीका बताया। जीवन का लक्ष्य ऊंचा व जीवन शैली नियमानुसार बनाएं। समाधि का अर्थ है जीवन के हर क्षेत्र में शांति में आनंद हो। अगर चित्त में समाधि नहीं है तो सारे ही अनुष्ठान असफल है।

अंतरविद्यालयी विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने दिखाई अपनी रचनात्मक कला व प्रतिभा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय एजी जैन हायर सेकेंडरी स्कूल में अंतर-विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें विभिन्न उन्नीस विद्यालयों के होनहार विद्यार्थियों ने अपनी वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह के विशिष्ट अतिथि एसएस जैन एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष पदमचंद चोरड़िया ने फीता काटकर किया। चोरड़िया ने विद्यालय के अभिभावक के रूप में कार्यक्रम की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा प्रत्येक मॉडल की बारीकी से अवलोकन किया। समारोह के मुख्य अतिथि चेन्नई नार्थ के टीआई स्कूल के प्रधानाध्यापक डॉ डी. सेंथिल कुमार थे जिन्होंने विज्ञान के महत्व और नवाचार की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा, ज्ञान का दीपक सदा जलता रहे, यही सच्चे विज्ञान की पहचान है।

इस प्रदर्शनी को तीन वर्गों में विभक्त किया गया था, प्रथम वर्ग कक्षा 6 से 8, द्वितीय वर्ग कक्षा 9 और 10 तथा तृतीय वर्ग कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों ने अपने माडल प्रदर्शित किए तथा सबका ध्यान आकर्षित किया। विद्यार्थियों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा पर्यावरण संरक्षण,स्वास्थ्य, आरोग्यता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसे विविध विषयों पर अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। सभी वर्ग में विजेता विद्यार्थियों का प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। विशिष्ट पुरस्कार एजी जैन हायर सेकंडरी स्कूल के कक्षा दसवीं के मास्टर सार्थक पांडेय, मुकेश कृष्णा एवं मास्टर तनेश सिंह को दिया गया। सभी पुरस्कार राशि गौतमचंद बोहरा द्वारा प्रायोजित थी। विद्यालय के पत्राचारक गौतमचंद गोठी और सचिव दलजीतसिंह ढढा ने धन्यवाद दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्या डॉ जयश्री ने सभी विजयी विद्यार्थियों की सराहना की।

वैष्णव बाजार 2024 का आयोजन आज से, तैयारियां पूर्ण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

चेन्नई। स्थानीय द्वारकादास गोवर्धनदास वैष्णव कॉलेज में 2 दिनों तक चलने वाला मेला 'वैष्णव बाज़ार-2024'का आयोजन आज से शुरु होगा जो 24 अगस्त तक आयोजित होगा। वैष्णव बाजार लगभग 200 स्टालों लगेंगे जिसमें विद्यार्थियों की रचनात्मकता को व्यावसायिक उद्यम के रूप में देख सकेंगे। कॉलेज के ईडी सेल, उद्यमिता द्वारा आयोजित डीजी वैष्णव कॉलेज का यह प्रमुख कार्यक्रम कॉलेज के सचिव अशोककुमार मूँदड़ा के मार्गदर्शन व प्राचार्य डॉ एस सन्तोष बाबू के निर्देशन व ईडी सेल की संयोजक प्रो. वी गायत्री की निगरानी में हो रहा है।

इस मेले में खाने-पीने और खेलों से लेकर विभिन्न एक्सेसरीज के स्टॉल होंगे। वैष्णव बाजार सिर्फ 50 रुपये के प्रवेश टिकट के साथ जनता के लिए खुला है। वैष्णव बाजार के पांचवें संस्करण को लेकर विद्यार्थियों व कॉलेज प्रबंधन में विशेष उत्साह है।

मासखमण तपस्वियों का किया गया अभिनन्दन समारोह

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

मंड्या। शहर के तेरापंथ भवन में चातुर्मासार्थ विराजित साध्वीश्री संयमलताजी के सान्निध्य में मासखमण तप के तपस्वी का अभिनंदन किया गया।

इस मौके पर साध्वीश्री ने कहा कि भाद्रव का महिना सब महीनों में महत्त्वपूर्ण है। प्राकृतिक, लौकिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व संघीय दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। यह माह पर्वो व त्यौहारों से सुसज्जित है, तप करने का मौसम है भाद्रव माह। जो समय को पहचान लेता है वह जीवन को अच्छा व सुंदर बना सकता है। साध्वीश्री के प्रेरणा से उषा अच्छा, ललिता संचेती, सोनल संचेती एवं संतोष भंसाली ने एकासन के मासखमण किए और आगे बढ़ रही है। अनुमोदना में साध्वी मार्दवाश्रीजी ने गीत प्रस्तुत किया।

डिजिटल रूप में भी पढ़ें दक्षिण भारत हिन्दी दैनिक www.dakshinbharat.com

Published by Bhupendra Kumar on behalf of New Media Company, Arihant Plaza, 2nd Floor, 84-85, Wall Tax Road, Chennai-600 003 and printed by R. Kannan Adityan at Deviyin Kanmani Achagam, 246, Anna Salai, Thousand Lights, Chennai-600 006.
Regn No. RNI No. : TNHIN / 2013 / 52520 **Editor : Bhupendra Kumar** (Responsible for selection of news under PRB Act.). Group Editor - Shreekant Parashar.
Reproduction of any matter from this newspaper in whole or in part or any such manner without prior written permission from the publisher is strictly prohibited and punishable by law.